

वर्ष-11, अंक-12, सितम्बर-2026

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका



BRICS
INDIA 2026

भारत का बढ़ता कद

मजबूत होता 'ब्रांड मोदी'





मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,

भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में मथुरा के कारागार में जब नंदलाला का प्राकट्य हुआ, तब असत्य और अन्याय के अंधकार के बीच सत्य और धर्म का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं मन को आनंदित करने वाली कथाएं मात्र नहीं, बल्कि उनमें गहन आध्यात्मिक संदेश निहित हैं। माखन चोरी में सहजता और निश्छलता, गोप-गोपियों के साथ उनकी आत्मीयता में प्रेम और समरसता तथा कालिय नाग के दमन में अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश मिलता है। इस पावन अवसर पर आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (4 सितम्बर, 2026) की हृदय से शुभकामनाएं।

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें बताता है कि समाज की शक्ति सामूहिक सहकारिता में निहित है। गोवर्धन पर्वत धारण कर उन्होंने प्रकृति, पशुधन और कृषि-आधारित जीवन के संरक्षण तथा सामूहिक एकजुटता का संदेश दिया। वृंदावन से लेकर बरसाना की राधारानी और नंदगांव की प्रेममयी स्मृतियों तक, ब्रज की धरती आज भी उस दिव्य चेतना को अपने कण-कण में संजोए हुए है।

श्रीकृष्ण कुलीनता के नहीं, समरसता के प्रतीक हैं। वे समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ खड़े रहे। वे द्वारकाधीश हैं, तो सुदामा के आत्मीय मित्र भी। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और सुदामा के साथ उनकी मित्रता ने बताया कि सच्चे संबंध पद, प्रतिष्ठा और संपन्नता से नहीं, आत्मीयता से बनते हैं। यही समरसता, समानता और आत्मीयता आज के समाज की आवश्यकता है।

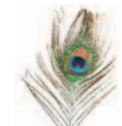
योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें लोककल्याणकारी शासन की मूल भावना की प्रेरणा भी देता है। अन्याय का प्रतिकार, धर्म की रक्षा, निर्बल का संरक्षण और लोकमंगल उनके जीवन-दर्शन के प्रमुख आधार रहे। आज इसी भाव के साथ हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश, प्रतिभासंपन्न निपुण युवाओं को काम, अन्नदाताओं को सहारा एवं बेटीयों को बेटों के समान आगे बढ़ने का अवसर, लोककल्याण की इसी भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है।

गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कर्म, ज्ञान और कर्तव्य का जो मार्ग दिखाया, वह केवल किसी एक युग के लिए नहीं है। दैनंदिन जीवन की प्रत्येक चुनौती में इससे बड़ा मार्गदर्शन शायद ही कुछ और हो। निष्काम कर्म, सत्य के प्रति निष्ठा और लोकमंगल की भावना हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है।

उत्तर प्रदेश की धरती श्रीकृष्ण की लीलाओं और संदेशों की पावन भूमि है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव हमारी सनातन सांस्कृतिक चेतना के जीवंत केंद्र हैं। आइए, इस जन्माष्टमी पर अपनी विरासत के संरक्षण, सामाजिक समरसता और विकसित एवं गौरवशाली उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें तथा श्रीकृष्ण के सत्य, धर्म, कर्म और लोकमंगल के संदेश को अपने जीवन में उतारें।

आपका

योगी आदित्यनाथ



जय कन्हैयालाल की



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश



UPGovtOfficial



CMOUttarpradesh



CMOfficeUP



वर्ष - 11 अंक - 12

सितम्बर - 2026

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक

अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक

स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित्त त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार

विजय अरोड़ा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी

डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड

रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार

कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर
एन्टरप्राइजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रियल एरिया साउथ साईड
जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर गाउँड प्लोर 150,
दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611

ई-मेल: winews.in@gmail.com

वेबसाइट: www.winews.in

सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से
सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा
किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद
न्यायालय मान्य होगा।



कवर स्टोरी पेज-28



उत्तर प्रदेश में सनातन
और विकास की गूंज

पेज
03



मायावती का बड़ा फैसला:
'आजाद' हुए आकाश आनंद

पेज
12



रामदूत अतुलित बल
धामा... हनुमान अंश

पेज
52



राजनीतिक विरोध या चरित्र-
हन्नन? अखिलेश यादव के एआई
वीडियो ने खड़े किए गंभीर

पेज
08



सपा की नई सोशल जीनियरिंग:
डिपल, पीडीए और ब्राह्मण दांव

पेज
14



राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का
दमदार प्रदर्शन, 13 स्वर्ण
सहित जीते 39 पदक

पेज
54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक
कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 / 9813221734 पर सम्पर्क करें।

ब्रिक्स के भविष्य की राह

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन- 2026 में 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को अपनाया जाना इस समूह की बदलती भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में पश्चिम एशिया का संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध, व्यापारिक तनाव, शुल्क नीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। घोषणापत्र का सबसे अहम पहलू बहुपक्षीय और अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देना है। इसे भारत के प्रयासों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने की नजर से देखा जा रहा है।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग लंबे समय से भारत की प्राथमिकता रही है। इसका मतलब है कि विश्व स्तर के निर्णय केवल कुछ शक्तिशाली देशों तक सीमित न रहें, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज भी प्रभावी ढंग से सुनी जाए। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों की संयुक्त घोषणापत्र पर सहमति बनाने में सफलता को भी भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

घोषणापत्र में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए उसके वित्तपोषण, सीमा पार से घुसपैठ और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह लंबे समय से आतंकवाद को वैश्विक चुनौती के रूप में उठाता रहा है।

हालांकि घोषणापत्र की वास्तविक सफलता इससे तय होगी कि सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ साझा नीति को व्यवहार में कितना उतारते हैं। ब्रिक्स देशों ने अमेरिका की एकतरफा शुल्क नीति पर भी गहरी चिंता जताई और गैर-शुल्क व्यापारिक उपायों की वकालत की। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, सीमा-पार भुगतान और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इसी का हिस्सा है। वर्तमान वैश्विक व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद के बीच यह संदेश महत्वपूर्ण है।

तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ढांचे और सतत विकास भी भारत के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। इसके मद्देनजर भारत ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता पर जोर दिया है और इसे ब्रिक्स देशों के घोषणापत्र में भी जगह दी गई है। स्पष्ट है कि ब्रिक्स अब स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, पर्यावरण और मानव विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया के संघर्ष पर घोषणापत्र में संयम, संवाद और कूटनीति का आह्वान एकजुटता को दर्शाता है।

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अलग-अलग हितों वाले देशों की मौजूदगी के बावजूद साझा दृष्टिकोण पर सहमति बनना दुनिया के लिए एक सार्थक संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। उनका यह आह्वान कि वैश्विक दक्षिण को हानियमों का पालन करने वाले 'के बजाय' नियम तय करने वाला 'बनना होगा, दरअसल पश्चिम के उन देशों के लिए संदेश है, जिनकी वैश्विक निर्णयों में भागीदारी ज्यादा रहती है। बहरहाल, यदि ब्रिक्स साझा घोषणापत्र को व्यावहारिक रूप देता है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है।



ललित कुमार
सम्पादक

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग लंबे समय से भारत की प्राथमिकता रही है। इसका मतलब है कि विश्व स्तर के निर्णय केवल कुछ शक्तिशाली देशों तक सीमित न रहें, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज भी प्रभावी ढंग से सुनी जाए।

उत्तर प्रदेश में सनातन और विकास की गूंज



उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही सभी राजनैतिक दलों ने अपना गुणा-भाग करके उसके आधार पर पिच बनानी आरम्भ कर दी है। अभी तक जो राजनैतिक अनुमान सामने आए हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के मध्य सीटों के तालमेल पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है जिसके कारण इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में भ्रम व असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनावी तैयारी करते हुए सपा ने कार्यकर्ताओं की ड्रेस का रंग भी बदल डाला है।

भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और

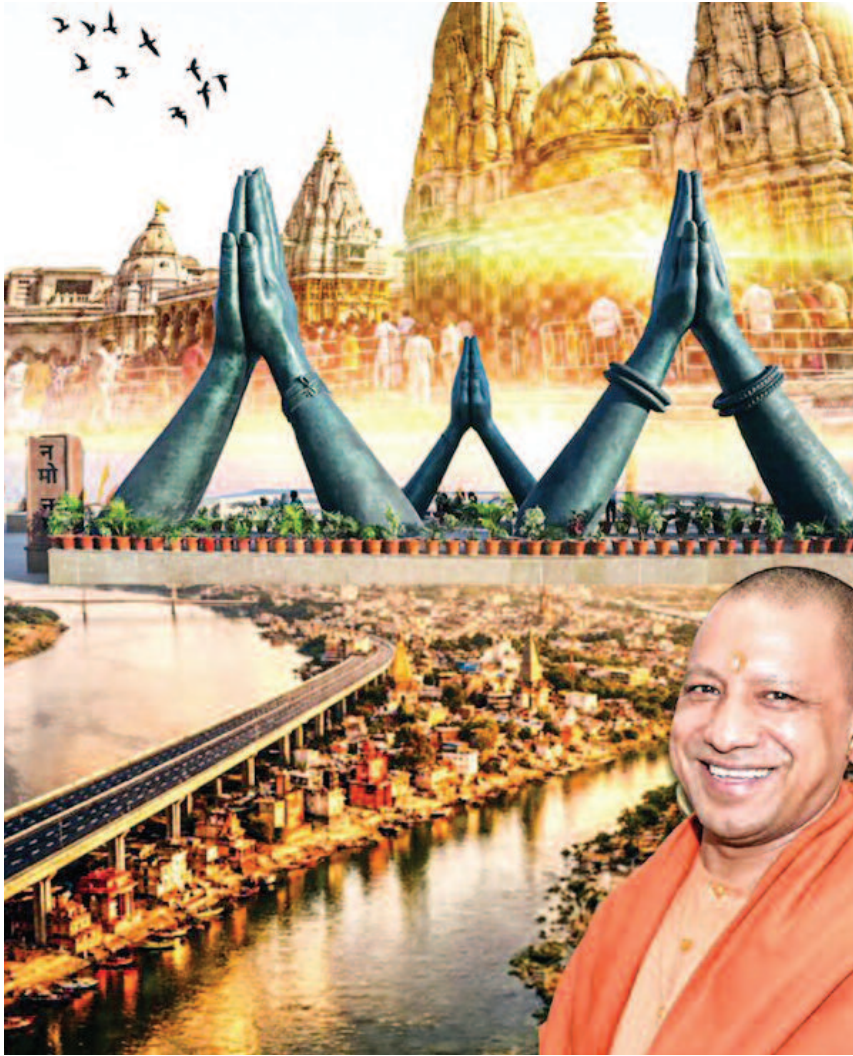


अनादि शुक्ल

अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं। भाजपा ने 2027 के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें हर बूथ को मजबूत करना होगा। कोई बूथ छूटना नहीं चाहिए। सभी जातियों को साधने का मंत्र दिया गया है। संख्या चाहे कम हो या ज्यादा लेकिन कोई जाति अछूती न रहे। हमें सबको जोड़ना होगा। भाजपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व व

उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाती के माध्यम से, मंच से तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी जनता के साथ संवाद बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का जनता दरबार तो नियमित है ही। वह अयोध्या, मथुरा, काशी की भूमि से सनातन का संदेश भी दे रहे हैं। योगी स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों से मिल रहे हैं। योगी ने सार्वजनिक संवाद के मंचीय भाषण और योजनाओं के शुभारंभ से आगे बढ़कर युवाओं, छात्रों, लाभार्थियों से संवाद का विस्तार किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा का दो दिवसीय दौरा कर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अयोध्या में



दिव्य व भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर है और अब श्रीकृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति का समय आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से अवध से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक समस्त क्षेत्र को सनातन के रंग में रंग दिया और अपने मतदाता को बता दिया कि अब अगला चरण श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का ही है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने दो दिन बिताए।

परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए सपा सरकार के काले कारनामों को उजागर किया और समा बांध दिया। अपने भाषण में योगी ने कहा कि प्रदेश में 2017 के पूर्व उत्सव नहीं उपद्रव होता था। पूर्व की सरकार दंगाइयों को सम्मान देती थी। अब दंगामुक्त प्रदेश में भारी संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सनातन की आभा निरंतर बढ़

रही है।

आज काशी विश्वनाथ धाम भव्यता और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में बाबर ने 128 में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर को तोड़कर गुलामी का ढांचा बनवा दिया लेकिन इससे रामनवमी, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा सावन का झूला मेला नहीं रुका। सनातन की आभा निरंतर बढ़ती रही और संघर्षों का जज्बा पैदा करती रही। इसी का परिणाम है कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम का दिव्य व भव्य मंदिर बन गया है।

मुख्यमंत्री मथुरा में दो दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने के बाद लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर उन्होंने गोरखपुर में भी जन्माष्टमी समारोह में भाग लेकर हिंदू समाज को स्पष्ट संकेत दिया कि भाजपा की योजना इस बार मंडल व

कमंडल दोनों को अपने में समाहित कर लेने की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जहां सनातन की आभा बढ़ रही है वहीं विकास की गूंज भी लगातार सुनाई दे रही है। भाजपा सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से उन सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास कर रही है जो उसके वोट प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक है। प्रदेश के शिक्षकों के लिए सुविधाओं की घोषणा, 60 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा तथा समाजिक पेंशन में वृद्धि के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सेविकाओं का मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया गया है जबकि सहायिका का मानदेय 6 हजार की जगह 8 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, स्मार्टफोन तथा साइडियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

अयोध्या में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज से 9 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हालात में थे और बच्चे खुद टाट पट्टी लेकर पढ़ने के लिए आते थे, आंगनबाड़ी केंद्र अस्त व्यस्त रहते थे, समय से पोषाहार नहीं मिलता था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सेविकाओं को सम्मानित भी किया। योगी ने यहां पर भी सनातन को जोड़ लिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं की तुलना माता यशोदा से करी। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस इस बात से हैरान है कि रैन बसेरा निषादराज के नाम से कैसे बन गया ? यहां के भोजनालय शबरी माता के नाम से कैसे बन गए ? अयोध्याधाम में रामलला विराजमान होने को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है किंतु सपा और कांग्रेसी खेमे में वीरानी छई हुई है। वे भौंचक हैं कि अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर कैसे बन गया। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विकास कैसे हो गया तथा सड़केन कैसे चौड़ी हो गयीं। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बन गया ?

आगामी विधनसभा चुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और वह हर वर्ग व जाति को साधते हुए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है इसके इतर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन सीटों के तालमेल पर ही अटका है।

चुनावी बिसात और बदलते समीकरण

सपा की इस रणनीति के जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी खामोश नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी संगठन मशीनरी को पूरी तरह से चुनावी मोड में डाल दिया है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर का ढांचा माना जाता है।



उत्तर प्रदेश की राजनीति को भारतीय लोकतंत्र का हृदयस्थल माना जाता है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ के गलियारों से होकर गुजरता है, यही कारण है कि देश के इस सबसे बड़े सूबे में होने वाली हर छोटी-बड़ी राजनीतिक हलचल का असर राष्ट्रीय फलक पर साफ दिखाई देता है। वर्ष 2026 की समाप्ति के करीब आते ही और 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच शह-मात का खेल पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सूबे की राजनीतिक जमीन



रवि जैन

को जो नई शकल दी थी, उसके बाद हर दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होकर इतिहास रचने की कवायद में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने 'PDA' (पिछड़ा,

दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे दस साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इस बार का चुनाव केवल पारंपरिक नारों या वादों पर आधारित नहीं रहने वाला, बल्कि यह जमीन पर रची जा रही नई सामाजिक और गठबंधन राजनीति की प्रयोगशाला बनने जा रहा है।

इस राजनीतिक उठापटक और नए समीकरणों के निर्माण के बीच हाल ही में लखनऊ से एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक खबर सामने आई, जिसने राज्य के सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और



पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच लखनऊ में लगभग 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक चली बंद कमरे की मैराथन मुलाकात ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस मुलाकात के मायने केवल एक शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह 2027 के महासमर से पहले उत्तर प्रदेश की युवा और छात्र राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आशुतोष रांका और अखिलेश यादव के बीच हुई इस चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मुद्दे, लगातार होती परीक्षाओं के पेपर लीक, बेरोजगारी, छात्रों की समस्याएं और उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट जैसे विषय शामिल रहे।

पार्टी के भीतर और बाहर इस मुलाकात को 'प्लान 2027' के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया और बेहद जागरूक मतदाता वर्ग तैयार हो चुका है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 'जेन-जी' या पहली बार मतदान करने वाले युवा कहते हैं। यह युवा वर्ग पारंपरिक जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाओं और आधुनिक अवसरों की मांग कर रहा है। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि केवल पारंपरिक मुस्लिम-

अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि केवल पारंपरिक मुस्लिम-यादव समीकरण या केवल सामान्य गठबंधनों के बूते भाजपा जैसी विशाल और साधन-संपन्न चुनावी मशीनरी को मात देना असंभव है।

यादव समीकरण या केवल सामान्य गठबंधनों के बूते भाजपा जैसी विशाल और साधन-संपन्न चुनावी मशीनरी को मात देना असंभव है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा अब छोटे-छोटे वैचारिक समूहों, छात्र संगठनों और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को अपने पाले में लाकर भाजपा के उस युवा वोट बैंक में संघ लगाना चाहती है, जो कभी भगवा दल की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। रांका और अखिलेश यादव की यह मुलाकात इस बात की तस्दीक करती है कि विपक्ष इस बार युवाओं के आक्रोश को एक ठोस राजनीतिक वोट बैंक में बदलने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है।

हालांकि, इस मुलाकात पर भाजपा ने भी

फौरन तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस नीति या विकास का एजेंडा नहीं है, इसलिए वह केवल भ्रम फैलाने और छोटे-छोटे संगठनों के सहारे अपनी डूबती नैया बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकार इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके मूल में युवाओं और छात्रों का आंदोलन या उनका असंतोष ही रहा है। ऐसे में सीजेपी जैसी युवा केंद्रित ताकतों और सपा का करीब आना भविष्य के एक नए और बड़े सामाजिक-राजनैतिक मोर्चे की बुनियाद रख सकता है।

यदि हम उत्तर प्रदेश की समूची राजनैतिक बिसात पर नजर डालें, तो इस समय सबसे बड़ा टकराव नैरेटिव यानी विमर्श गढ़ने को लेकर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार 'आरक्षण' और 'संविधान' को अपनी राजनीति के केंद्र में रख दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को 'संविधान बचाओ' के नारे से जो अप्रत्याशित लाभ मिला था, अखिलेश यादव उसे 2027 तक कायम रखना चाहते हैं। हालिया महीनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की स्थिति, 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद और पिछड़े-

दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर सपा ने एक आक्रामक रुख अखिलेश किया है। अखिलेश यादव लगातार जनसभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान सत्ताधारी दल दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इस नैरेटिव के जरिए सपा सीधे तौर पर भाजपा के गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित वोट बैंक पर निशाना साध रही है, जिसने पिछले एक दशक से भाजपा की जीत में रीढ़ की हड्डी का काम किया है।

सपा की इस रणनीति के जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी खामोश नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी संगठन मशीनरी को पूरी तरह से चुनावी मोड में डाल दिया है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर का ढाँचा माना जाता है। पार्टी ने इस बार कागजी दावों को खारिज करते हुए हर एक बूथ कमेटी का भौतिक सत्यापन शुरू किया है। खासकर उन बूथों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ पिछले चुनाव में विपक्ष को बढ़त मिली थी। इसके साथ ही, भाजपा सरकार अपनी कानून-व्यवस्था की सख्त छवि, बुनियादी ढाँचे का विकास (जैसे एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे) और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के एक बड़े नेटवर्क के भरोसे मैदान में उतर रही है। भाजपा का मानना है कि विकास और सुशासन का उनका यह 'डबल इंजन' मॉडल विपक्ष के जातिगत ध्रुवीकरण के प्रयासों को विफल कर देगा।

लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन के भीतर की आंतरिक खींचतान भी पूरी तरह सतह पर आ चुकी है। गठबंधन में शामिल छोटे दल जैसे निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद, अपना दल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल और सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और सीटों के सम्मानजनक बंटवारे के लिए भाजपा पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के भावुक होने और आंसुओं के छलकने की घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी उबाल ला दिया था। जहाँ संजय निषाद ने इसे अपने समाज को हक न मिल पाने की पीड़ा बताया, वहीं अखिलेश यादव ने तुरंत इस पर तंज कसते हुए इसे भाजपा के साथ जाने का 'पश्चाताप



और प्रायश्चित' करार दे दिया। यह घटना दशार्ती है कि निषाद और अन्य अति-पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को लेकर दोनों पक्षों में कितनी जबर्दस्त रस्साकशी चल रही है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि निषाद समाज भी उनके 'PDA' का एक अभिन्न हिस्सा है और यदि उनकी सरकार आती है, तो वे जातीय जनगणना कराकर हर समाज को उसका वास्तविक हक देंगे। इतिहास

दूसरी तरफ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का 'इंडिया' गठबंधन भी एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यद्यपि अखिलेश यादव और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बार-बार यह दोहराया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर सीटों के बंटवारे और प्रादेशिक नेतृत्व को लेकर दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच महत्वाकांक्षाओं का टकराव साफ दिखाई देता है। कांग्रेस जहां

लोकसभा चुनाव के उत्साह के बाद उत्तर प्रदेश में अपने पुराने गौरव को हासिल करने के लिए अधिक सीटों की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखते हुए कांग्रेस को सीमित सीटों पर समेटने की रणनीति बना रही है। इसके अतिरिक्त, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती की खामोशी और उनकी अंदरूनी बैठकें भी इस त्रिकोणीय मुकाबले को और दिलचस्प बना रही हैं। मायावती अपने खिसकते दलित वोट बैंक को सहेजने के लिए नए सिरे से कैडर कैंप आयोजित कर रही हैं। यदि बसपा अपने पारंपरिक वोट को बचाने में सफल रहती है, तो इसका सीधा नुकसान सपा-कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, जिससे अंततः भाजपा को लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी।

सियासत के इस खेल में शह और मात के मोहरे बिछ चुके हैं। जनता शांत है, लेकिन वह हर दल की चालों को बहुत बारीकी से देख रही है। रोजगार की तलाश में भटकता युवा, महंगाई से जूझता आम नागरिक और अपने अधिकारों के प्रति सजग होता जातियों का समूह ही अंततः यह तय करेगा कि 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर किसका राजतिलक होगा। फिलहाल, राजनैतिक दलों की यह सरगमी और रणनीतिक मुलाकातों का दौर यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनावी संग्राम बेहद रोमांचक, अप्रत्याशित और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।



राजनीतिक विरोध या चरित्र-हनन ?

अखिलेश यादव के एआई वीडियो ने खड़े किए गंभीर



आलम वारसी

राजनीतिक बहसों में मतभेद और तीखे हमले भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब विरोध का माध्यम व्यक्तिगत आक्षेप और किसी की गरिमा व धार्मिक आस्था को आहत करने वाले फर्जी आधुनिक साधनों तक पहुंच जाए, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से निर्मित एक वीडियो प्रस्तुत करने का मामला इसी विषय

को रेखांकित करता है। डीपफेक और एआई की मदद से किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अथवा किसी धार्मिक पीठ के प्रमुख का विकृत रूप पेश करना केवल एक राजनीतिक विरोधी पर प्रहार भर नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन में शुचिता, सामान्य शिष्टाचार और नैतिक सीमाओं के पतन को भी दर्शाता है।

संवैधानिक और पीठ की गरिमा का अनादर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र 'गोरक्षपीठ' के पीठाधीश्वर भी हैं। भारत की संत परंपरा और श्रद्धालुओं के मन में इस पीठ का विशेष और पूजनीय स्थान है।

राजनीतिक विरोध की अपनी सीमाएं होती हैं। नीतियों, कानून-व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार पर सवाल पूछना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। किंतु, एआई तकनीक के जरिए किसी पीठाधीश्वर के चरित्र और आस्था से जुड़ी झूठी तस्वीरें गढ़ना सार्वजनिक विमर्श के गिरते स्तर का, पतन का प्रतीक है।

निष्कलंक है योगी आदित्यनाथ की छवि

सपा कार्यालय में घटित इस घृणित कार्य का सबसे विरोधाभासी पहलू यह है कि इसमें ऐसे व्यक्ति पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया, जिसका व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह और निष्कलंक रहा है। आप उनसे धार्मिक या राजनीतिक मतभेद रख सकते

हैं। लेकिन वह चाहें गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में सामने आएँ अथवा सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में, आप योगी आदित्यनाथ पर कदाचार या विलासी जीवन जीने का आरोप नहीं लगा सकते। वह एक कॉरपोरेट सीईओ की कार्यशैली में पूरी कुशलता से प्रदेश का संचालन करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली एक संत या संन्यासी जैसी ही रहती है। राम मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह स्वतंत्र ट्रस्ट के अधीन है, लेकिन ट्रस्ट का अनुरोध पत्र मिलते ही उन्होंने चढ़ावा प्रकरण पर एसआईटी का गठन कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके बावजूद अगर कोई योगी आदित्यनाथ को इस प्रकरण से जोड़ने का भोंडा प्रयास करता दिखाई दे तो इसे चुनावी लाभ के लिए पतन की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है।

यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है कि गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में गुरु गोरखनाथ धाम का संपूर्ण नियंत्रण योगी आदित्यनाथ के पास है। पीठ को नाथ संप्रदाय के देश-दुनिया में बसे अनुयायियों व अन्य भक्तों से नियमित चढ़ावा प्राप्त होता होगा। साधारण गेरुआ वस्त्र पहनने, साधारण भोजन करने और साधारण बिस्तर पर सोने वाले योगी आदित्यनाथ आखिर क्या करते हैं इस धनराशि का? सपा प्रमुख ने इस बारे में एक क्षण भी सोचा होता तो वह ऐसा आरोप लगाने से पहले सौ बार सोचते। उन्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु गोरखनाथ धाम प्रतिदिन हजारों लोगों का पेट भरने के अलावा विगत कई वर्षों से अनेक चैरिटेबल स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालयों का संचालन और समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। अनगिनत लोगों की रोजी-रोटी गुरु गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी है। योगी आदित्यनाथ के साथ आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन उनकी जीवन-शैली व ईमानदारी पर सवाल उठाना मानसिक दिवालियापन के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता।

योगी आदित्यनाथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर कभी समझौता करते नहीं दिखाई देते, चाहें भले ही उन्हें इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। बाजार का नियम कहता है कि उत्पाद बनाने वाला उसे बेचने के लिए कोई कसर न छोड़े। लेकिन, जिस मुख्यमंत्री के राज्य में देश के 55 फीसदी मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा हो, वह अपने तमाम संवादों में बच्चों, विद्यार्थियों, युवाओं के साथ-

साथ अभिभावकों से स्मार्टफोन से दूरी बनाने की अपील करता है। वह राजस्व की चिंता किए बगैर अपनी सभाओं में युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराता है। वह लिकर व ड्रग माफिया की कमर तोड़ता है। ऐसे योगी को व्यसन के साथ जोड़कर दिखाना साबित करता है कि लगातार दो हार के बाद अखिलेश यादव राजनीतिक लड़ाई लड़ने की इच्छाशक्ति खो बैठे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया वह एक थका हुआ, हारा हुआ, कमजोर व्यक्ति ही कर सकता था।

तकनीक का दुरुपयोग और डीपफेक का खतरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का मुख्य उद्देश्य समाज को सशक्त बनाना, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता लाना और दैनिक जीवन को सुगम बनाना है। लेकिन जब राजनीतिक दल इस तकनीक का उपयोग अपने विरोधियों का चरित्र-हनन करने या भ्रामक नैरेटिव बनाने के लिए करने लगते हैं, तो यह सीधे तौर पर समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। यह घटना दशार्ती है कि आने वाले समय में चुनावी स्पर्धा और राजनीतिक जंग में डीपफेक तथा फेक मीडिया का दुरुपयोग किस कदर बढ़ सकता है। अगर ज़िम्मेदार नेता स्वयं इस तरह की सामग्री को अपनी आधिकारिक वाताओं में बढ़ाना शुरू करेंगे, तो आम जनता में तकनीक के प्रति अविश्वास और समाज में वैमनस्य ही बढ़ेगा।

‘शुचिता’ और ‘शिष्टाचार’ की आवश्यकता

भारतीय राजनीति का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, जहां वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेताओं



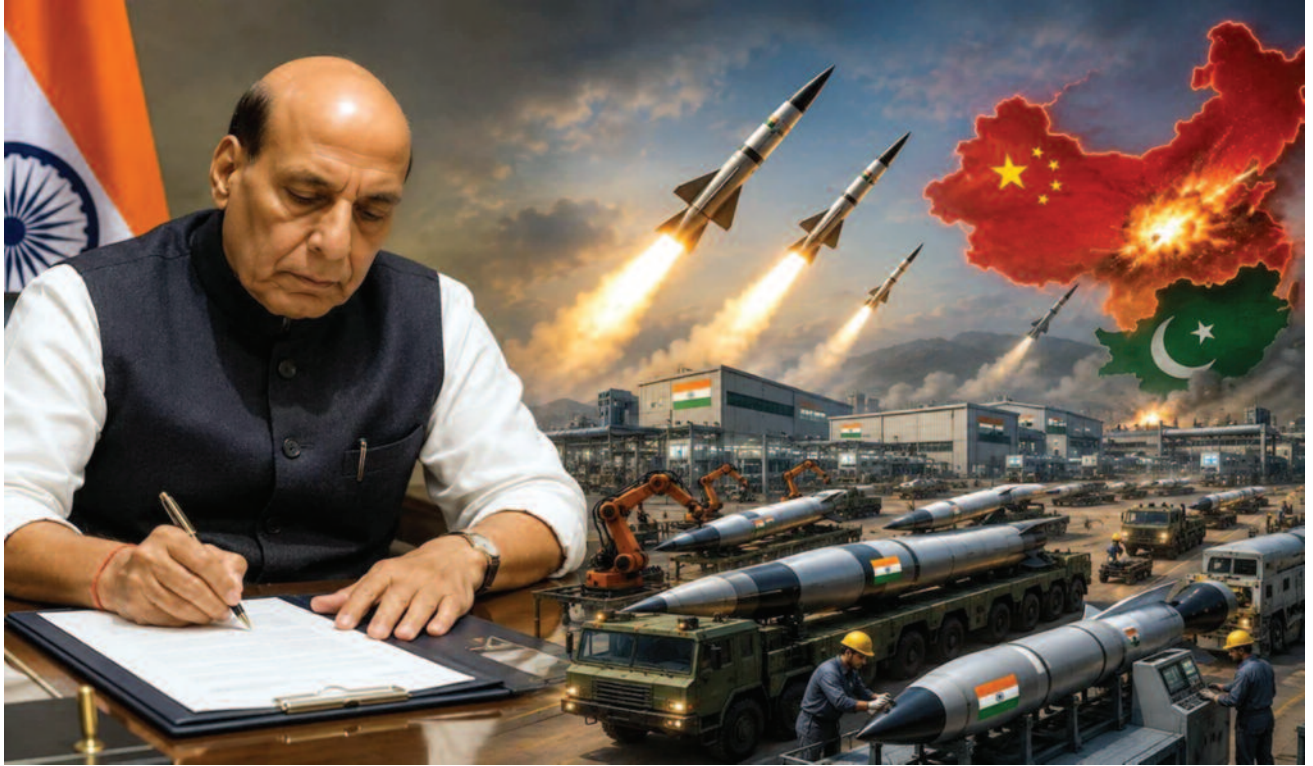
के बीच व्यक्तिगत सम्मान और शिष्टाचार बना रहता था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को कभी भी व्यक्तिगत कटुता या धार्मिक भावनाओं को टेस पहुंचाने का साधन नहीं बनाया जाता था। जब शीर्ष स्तर के नेता राजनीतिक लाभ के लिए मयादाओं को लांघते हैं, तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं और जनसामान्य तक नकारात्मक रूप से जाता है। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक आचरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी है।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने की तकनीक नहीं है। यह स्वतंत्र विचार, निष्पक्ष सूचना, जनविश्वास और नागरिक के विवेकपूर्ण निर्णय पर टिका होता है। इसलिए यदि एआई का इस्तेमाल मतदाता की सोच को प्रभावित करने, झूठी सूचनाएं फैलाने, विरोधी विचारों को बदनाम करने अथवा चुनाव जीतने के लिए जनमत को कृत्रिम रूप से मोड़ने में किया जाएगा, तो चुनाव भले ही तकनीकी रूप से सफल हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। तकनीक की शक्ति जितनी बढ़ रही है, उसके नैतिक उपयोग की ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बढ़नी चाहिए। एआई से तेज चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र केवल सत्य, विश्वास और स्वतंत्र विवेक से ही मजबूत किया जा सकता है। एआई मानव सभ्यता के लिए एक अद्भुत अवसर है। यह शिक्षा, शोध, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और शासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी और जनोन्मुख बना सकती है। लेकिन यही तकनीक यदि ज्ञान और विकास का साधन बनने के बजाय भ्रम, दुष्प्रचार, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और राजनीतिक स्वार्थ का हथियार बन जाए, तो इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनसमर्थन नीतियों, विकास के विजन और जनता के मुद्दों को उठाने से मिलता है, न कि विरोधियों की विकृत छवियां प्रस्तुत करके। एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग रचनात्मक कार्यों और विकास के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। नेताओं को चाहिए कि वे सार्वजनिक जीवन में संवाद का स्तर ऊंचा रखें, ताकि भावी पीढ़ी के समक्ष एक स्वस्थ, संयमित और लोकतांत्रिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। अफसोस है कि किसी ने अखिलेश यादव को यह नहीं बताया।

दुश्मनों पर दनादन बरसेंगी मिसाइलें

भारत में प्राइवेट कंपनी भी बनाएंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की Technology Transfer को दी मंजूरी



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत की युद्ध-तैयारी को नई धार देने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक निजी भारतीय कंपनियों को देने की मंजूरी देकर भारत ने चीन और पाकिस्तान को भी चौंकाने वाला संदेश दिया है। जहां चीन और पाकिस्तान में मिसाइल निर्माण मुख्यतः सरकारी रक्षा कंपनियों के हाथों में केंद्रित है, वहीं भारत अब सरकारी उपक्रमों के साथ-साथ निजी उद्योगों को भी इस सामरिक उत्पादन श्रृंखला में उतार रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में युद्ध की स्थिति में भारत के पास मिसाइल उत्पादन के कई स्रोत होंगे। यदि कभी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ दो मोर्चों पर संघर्ष



कपिल चौहान

की स्थिति बनी, तो भारत केवल अपने मौजूदा भंडार पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक औद्योगिक नेटवर्क के सहारे उत्पादन बढ़ाकर दे दनादन, दे दनादन मिसाइलों की मारक क्षमता बनाए रखने की स्थिति में होगा। यह फैसला केवल 'मेक इन इंडिया' नहीं, बल्कि युद्ध के समय मिसाइल स्प्लाई चेन को अटूट बनाए रखने की रणनीति है।

देखा जाये तो भारत ने अपनी रक्षा नीति में

एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया है, जो आने वाले वर्षों में देश की युद्ध क्षमता, सैन्य आपूर्ति श्रृंखला और सामरिक आत्मनिर्भरता की तस्वीर बदल सकता है। भारत की रक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है उसका अर्थ यह है कि देश अब रक्षा अनुसंधान को सरकारी प्रयोगशाला से निकालकर बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन में बदलना चाहता है।

इस नीति के दायरे में वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली, टैंक रोधी और सतह से सतह पर मार करने वाली अनेक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक उद्योग तक पहुंच सकती है। इसमें आकाश, नाग, VSHORADS, अस्त्र, रुद्रम, प्रलय और मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइलों जैसी प्रणालियां शामिल हैं।

मिसाइल तकनीक का हस्तांतरण पात्रता,

प्रमाणन और नियामकीय शर्तों के अधीन होगा। इसका सबसे बड़ा सामरिक लाभ यह है कि युद्ध के समय किसी एक सरकारी उत्पादन इकाई या सीमित आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम होगी और देश के भीतर व्यापक उत्पादन नेटवर्क तैयार किया जा सकेगा।

देखा जाये तो ईरान के साथ 2026 के संघर्ष ने दुनिया को एक कठोर सैन्य सबक दिया है। सबक यह है कि युद्ध में केवल मिसाइल तकनीक होना पर्याप्त नहीं है, उनके विशाल और लगातार भरते रहने वाले भंडार भी जरूरी हैं। CSIS के आकलन के अनुसार ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका के Patriot और THAAD इंटरसेप्टर भंडार पर भारी दबाव पड़ा; Patriot की उपलब्ध संख्या एक हजार से नीचे और THAAD लगभग 250 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। विश्लेषण में यह भी चेतावनी दी गई कि घटते भंडार अमेरिका को भविष्य के संघर्षों में इंटरसेप्शन के मामले में अधिक जोखिम लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

यही नहीं, कुछ आकलनों में अमेरिका द्वारा अपने पूर्व-युद्ध Patriot भंडार का लगभग दो-तिहाई तक इस्तेमाल होने की बात कही गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद Patriot और अन्य उन्नत इंटरसेप्टरों के भंडार को पुराने स्तर तक पहुंचाने में करीब तीन वर्ष या उससे अधिक लग सकते हैं। अन्य विश्लेषण यह भी बताते हैं कि Tomahawk जैसी मिसाइलों के नए उत्पादन में लंबा समय लगता है और उन्नत हथियारों की कमी दूर करना वर्षों का काम है।

इसके अलावा, इस तरह की भी रिपोर्टें आई कि अमेरिका को दूसरे देशों में मौजूद अपने सैन्य अड्डों से मिसाइलें वापस मंगवानी पड़ीं। रिपोर्टों में कहा गया कि मध्य-पूर्व में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी सैन्य नेटवर्क के संसाधनों, तैनाती और उत्पादन क्षमता पर भारी दबाव पड़ा और पेंटागन को भंडार भरने तथा उत्पादन तेज करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े। यही इस पूरे घटनाक्रम का वास्तविक रणनीतिक संदेश है कि यदि एक बड़ी शक्ति का मिसाइल भंडार एक क्षेत्रीय युद्ध से इतना दबाव महसूस कर सकता है, तो एक साथ दो मोर्चों या किसी बड़े शक्ति संघर्ष की स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

भारत के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी

है। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती वाले वातावरण में भारत किसी एक उत्पादन लाइन के भरोसे नहीं रह सकता। युद्ध लंबा खिंचा तो मिसाइलों का प्रश्न केवल 'कौन सी मिसाइल बेहतर है' नहीं, बल्कि 'कितनी जल्दी और कितनी संख्या में फिर बनाई जा सकती है' बन जाता है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग पहले ही कर चुका है। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष गतिविधियां खोलने और IN-SPACe जैसे ढांचे के बाद Skyroot Aerospace और Agnikul Cosmos ने सब-ऑर्बिटल लॉन्च का सफल प्रदर्शन किया। Dhruva Space के नैनो-सैटेलाइट PSLV मिशन से लॉन्च हुए, जबकि Pixxel ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। निजी कंपनियों को ISRO की सुविधाओं और तकनीकी समर्थन तक पहुंच भी दी गई।

अब रक्षा क्षेत्र, विशेषकर मिसाइल उत्पादन में वैसी ही औद्योगिक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश दिखाई दे रही है। DRDO के Development-cum-Production Partner मॉडल के तहत मार्च 2026 तक 134 कंपनियां भागीदार बन चुकी थीं, 2180 तकनीक हस्तांतरण समझौते हुए और 2,780 से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार उद्योग के उपयोग के लिए खोले गए। सरकारी एजेंसियां

साथ ही रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ने का आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट है। 2025-26 में भारत

का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत रही। रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पहुंच गया और भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। इस निर्यात में निजी क्षेत्र का योगदान 17,353 करोड़ रुपये, यानी 45.16 प्रतिशत रहा।

यही कारण है कि मिसाइल तकनीक हस्तांतरण को केवल औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय युद्ध तैयारी की नीति के रूप में देखना चाहिए। अधिक कंपनियां उत्पादन में उतरेंगी तो क्षमता बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला फैलेगी, टरटए जुड़ेंगे, तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और युद्धकाल में उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की संभावना मजबूत होगी।

बहरहाल, अब भारत का सामरिक लक्ष्य सिर्फ मिसाइल बनाना ही नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान उन्हें लगातार बनाते रहने की क्षमता हासिल करना है। अमेरिका-ईरान संघर्ष ने बता दिया है कि आधुनिक युद्ध में गोला बारूद और मिसाइलों का भंडार किसी भी महाशक्ति की कमजोर नस बन सकता है। भारत ने समय रहते इस सबक को समझ लिया तो DRDO की तकनीक और निजी उद्योग की उत्पादन क्षमता का यह गठजोड़ आने वाले दशक में भारत की सबसे बड़ी सामरिक ताकतों में से एक साबित हो सकता है।



मायावती का बड़ा फैसला 'आजाद' हुए आकाश आनंद

बसपा सुप्रीमो ने आकाश की 'दोहरी मानसिकता' पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका तर्क था कि अगर आकाश के लिए पार्टी और बहुजन आंदोलन से ज्यादा अहम पारिवारिक रिश्ते हैं तो फिर वह पार्टी के लिए प्रभावी ढंग से काम कैसे कर सकते हैं?



बहुजन समाज पार्टी की सियासत में एक बार फिर ऐसा उलटफेर हुआ है, जिसने पार्टी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है। जिस कवायद को आकाश आनंद के सियासी भविष्य की राह साफ करने की कोशिश माना जा रहा था, वही कुछ घंटों में उनके बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह बाहर होने की पटकथा बन गई। हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से 'पूरी तरह आजाद' कर दिया है। खास बात यह है कि मायावती ने यह फैसला आकाश के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास की घोषणा के तत्काल बाद लिया। यानी जिस शर्त को



हरेन्द्र शर्मा

आकाश की वापसी और राजनीतिक सक्रियता के रास्ते की आखिरी बाधा माना जा रहा था, वह शर्त पूरी हुई, लेकिन नतीजा उम्मीद के ठीक उलट निकला। अशोक सिद्धार्थ ने गुरुवार सुबह भावुक संदेश के जरिए राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि मायावती का आदेश उनके लिए पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों से ऊपर है। उन्होंने यह भी कहा कि आकाश ने करीब

दो दशक मायावती की देखरेख और मार्गदर्शन में बिताए हैं और उनके भीतर मायावती का हृदयबद्ध बहता है। सिद्धार्थ ने खुद पर आकाश को प्रभावित या गुमराह करने के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता की इतनी हैसियत ही कहां कि वह आकाश को गुमराह कर सके।

लेकिन बसपा सुप्रीमो के तेवर इससे नरम नहीं हुए। मायावती ने अपने दस सूत्रीय संदेश में साफ कर दिया कि मामला केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी का नहीं है, बल्कि निष्ठा, परिवार और राजनीतिक प्राथमिकताओं का है। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ पार्टी और बहुजन आंदोलन के हित से ज्यादा

पारिवारिक रिश्तों और निजी हितों को महत्व दे रहे हैं। मायावती का सबसे तीखा सवाल आकाश की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर था। उनका कहना था कि आकाश पहले उनके पोस्ट को लगातार रीपोस्ट करके अपनी राजनीतिक निष्ठा जताते रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ से जुड़े हालिया पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट नहीं किया, जबकि मायावती के मुताबिक वह पोस्ट खुद आकाश के राजनीतिक हित में था।

यहीं से बसपा सुप्रीमो ने आकाश की हृदोहरि मानसिकता पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका तर्क था कि अगर आकाश के लिए पार्टी और बहुजन आंदोलन से ज्यादा अहम पारिवारिक रिश्ते हैं तो फिर वह पार्टी के लिए प्रभावी ढंग से काम कैसे कर सकते हैं? मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के राजनीति छोड़ने के फैसले को सही कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि फैसला देर से लिया गया। उनका आरोप था कि अगर सिद्धार्थ को अपने दामाद के उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की सचमुच चिंता होती तो वह उसी वक्त राजनीति छोड़ने की घोषणा कर देते। देरी को मायावती ने सिद्धार्थ की महत्वाकांक्षा और नीयत पर सवाल उठाने का आधार बनाया।

दरअसल, आकाश आनंद पिछले कुछ वर्षों में बसपा की अगली पीढ़ी के चेहरे के तौर पर तेजी से उभरे थे। मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। लेकिन आकाश की राजनीतिक भूमिका बार-बार बदलती रही। तीन सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाया गया और अब पार्टी से ही 'आजाद' कर दिया गया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की आहट तेज हो चुकी है। बसपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि मायावती के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा और संगठन को नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाएगा। आकाश आनंद को इसी संक्रमण का संभावित चेहरा माना जा रहा था। अब उनके बाहर होने से बसपा की उत्तराधिकार की पूरी रणनीति फिर सवाल के घेरे में है।

इस बीच मायावती के छोटे भाई के बेटे ईशान आनंद की हाल के महीनों में उनके साथ बढ़ती मौजूदगी भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे बसपा में अगली पीढ़ी की कमान को लेकर अटकलें और तेज हो सकती हैं।

मायावती का यूपी चुनाव में क्या है प्लान, ईशान को मिलेगी कमान?



अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया, लेकिन इससे BSP में उनके दामाद आकाश आनंद की जगह नहीं बच पाई। गुरुवार को मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आनंद ने बहुजन आंदोलन से ज्यादा परिवार के प्रति वफादारी को अहमियत दी। यह फैसला 3 सितंबर को आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटाए जाने के एक हफ्ते बाद आया। मायावती ने पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका में वापसी को सिद्धार्थ के राजनीति से पूरी तरह हटने से जोड़ा था। जब यह घोषणा हुई, तो उन्होंने कहा कि यह बहुत देर से आया है।

ईशान पर भरोसा: इस माहौल में, आकाश के छोटे भाई ईशान आनंद द्वारा मायावती के बयान को तुरंत रीपोस्ट करने की खबर अहम हो जाती है। मायावती ने हाल ही में ईशान को पार्टी में अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। जहाँ आकाश का पहले वाले पोस्ट को रीपोस्ट न करना आलोचना का विषय बना, वहीं मायावती के रुख का समर्थन करने के लिए ईशान की तत्परता दोनों भाइयों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती है। अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने के चार दिन बाद, मायावती ने सोमवार को अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी के संगठन में एक अहम पद पर नियुक्त किया। इरट के पदाधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ईशान की बढ़ती भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गईं; इस बैठक में ईशान भी मौजूद थे। पार्टी के पदाधिकारियों का मानना है कि वह मायावती के उत्तराधिकारी हो सकते हैं और उनकी हालिया नियुक्ति इसी बात का संकेत है।

देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का यह फैसला महज एक पारिवारिक विवाद नहीं माना जाएगा। 2027 में मुकाबला बहुकोणीय होने की स्थिति में बसपा का हर फैसला उसके वोट बैंक, संगठन और सोशल इंजीनियरिंग पर असर डालेगा। आकाश जैसे युवा चेहरे की विदाई से पार्टी को जहाँ नई पीढ़ी से जुड़ने में चुनौती मिल सकती है, वहीं मायावती के सामने अब यह साबित करने की चुनौती होगी कि बसपा किसी

एक उत्तराधिकारी के भरोसे नहीं, बल्कि उनके अपने राजनीतिक नियंत्रण और संगठनात्मक ढांचे पर खड़ी है।

फिलहाल संदेश साफ है कि ससुर ने राजनीति छोड़ी, लेकिन दामाद की कुर्सी नहीं बची। और मायावती की बसपा में रिश्ते नहीं, राजनीतिक निष्ठा अंतिम कसौटी है। 2027 के रण में इस फैसले की असली कीमत और असर तब सामने आएगा, जब हाथी मैदान में उतरेगा।

सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग: डिंपल, पीडीए और ब्राह्मण दांव



एक बड़ा सियासी सवाल निकलता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं? फिलहाल सपा की राजनीति का केंद्रीय चेहरा अब भी अखिलेश यादव ही हैं। लेकिन राजनीति में हर बात की शुरुआत घोषणा से नहीं होती।



मोहम्मद असलम

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती से नहीं जीते जाते। यहां जाति, जज्बात, चेहरा और संदेश, इन चारों का सही तालमेल सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी पुरानी साइकिल में नए राजनीतिक पुर्जे लगाने में जुटे हैं। मकसद सपा को उसकी पुरानी छवि से बाहर निकालना है, जिसे विरोधी लंबे समय से एक खास सामाजिक दायरे और सत्ता

में कथित तौर पर आक्रामक राजनीति से जोड़ते रहे हैं। अखिलेश की नई रणनीति में जातीय समीकरण भी है, हिंदू प्रतीक भी हैं, पीडीए का विस्तार भी है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिंपल यादव के रूप में एक नया और अपेक्षाकृत शांत चेहरा भी है।

डिंपल की बढ़ती भूमिका और 'सॉफ्ट पॉलिटिक्स'

देखा जाये तो अब तक डिंपल यादव की राजनीति अपेक्षाकृत संयमित और सीमित सार्वजनिक दायरे में दिखाई देती रही है। लेकिन हाल के समय में उनकी सक्रियता बढ़ी है। संसद से लेकर राजनीतिक मुद्दों तक उनकी मौजूदगी ज्यादा मुखर हुई है। यही बदलाव महज सामान्य राजनीतिक सक्रियता नहीं, बल्कि सपा की व्यापक रणनीति का एक अहम हिस्सा भी माना जा सकता

है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर आवाज जितनी ऊंची होती है, राजनीति उतनी ही असरदार दिखाई जाती है। आरोप-प्रत्यारोप, तीखे बयान और मंचीय हमले यहां आम बात हैं। ऐसे माहौल में डिंपल की शैली अलग दिखाई देती है। यानि कम शोर, संयमित भाषा, सहज व्यवहार और टकराव की बजाय संवाद का अंदाज। यही वजह है कि सपा के लिए उनका चेहरा राजनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है। कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति में धार वही है, लेकिन उसके साथ डिंपल की राजनीति का एक 'सॉफ्ट टच' जोड़ा जा रहा है।

क्या डिंपल यादव हो सकती हैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा?

यहीं से एक बड़ा सियासी सवाल निकलता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं? फिलहाल सपा की राजनीति का केंद्रीय चेहरा अब भी अखिलेश यादव ही हैं। लेकिन राजनीति में हर बात की शुरुआत घोषणा से नहीं होती। कई बार किसी नेता की बढ़ती सक्रियता, बदलती भूमिका और सार्वजनिक स्वीकार्यता ही भविष्य के संकेत देने लगती है। डिंपल की कार्यशैली अखिलेश से अलग है। अखिलेश जहां सीधे राजनीतिक हमले

करने और भाजपा के खिलाफ आक्रामक विपक्षी राजनीति का चेहरा हैं, वहीं डिंपल अपेक्षाकृत शांत और संतुलित दिखाई देती हैं। उनकी यही अलग पहचान भविष्य में सपा के लिए एक अतिरिक्त राजनीतिक पूंजी बन सकती है। सरकार इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में अब कोई भी पार्टी महिलाओं को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। भाजपा अपनी महिला-केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी राजनीति के जरिए महिला वोटर्स पर लगातार पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी समझ चुका है कि सिर्फ जातीय समीकरणों से चुनावी लड़ाई पूरी नहीं होती। 'आधी आबादी' अब सिर्फ नारा नहीं, चुनावी समीकरण का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में डिंपल यादव सपा के लिए एक प्रभावी महिला चेहरा बन सकती हैं। उनकी शांत और सहज छवि उन महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती है, जो सपा को अब तक मुख्य रूप से पुरुष नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में देखती रही हैं। अगर पार्टी महिलाओं के लिए ठोस राजनीतिक कार्यक्रम और भरोसेमंद संदेश के साथ मैदान में उतरती है, तो डिंपल उस अभियान का स्वाभाविक चेहरा बन सकती हैं।

वैसे यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वह मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सपा को 2027 में महिला

मतदाताओं के बीच अपनी नई जमीन तैयार करनी है, तो डिंपल की भूमिका केवल एक सांसद या स्टार प्रचारक तक सीमित नहीं रह सकती। यूपी की राजनीति में जो नेता धीरे-धीरे अपनी जगह बनाता है, वह कई बार अचानक बड़े समीकरण का केंद्र बन जाता है। डिंपल के मामले में भी यही संभावना राजनीतिक चर्चा को दिलचस्प बनाती है।

2027 और सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग

अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में बने राजनीतिक माहौल को 2027 की सत्ता तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पुराने समीकरण काफी नहीं होंगे। दलित राजनीति की जमीन में बदलाव आया है, पिछड़ों के भीतर भी कई परतें हैं और सवर्ण मतदाताओं को लेकर नई राजनीतिक संभावनाएं तलाशनी पड़ रही हैं। यहीं से सामने आता है पीडीए का विस्तार। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए सपा की नई राजनीतिक रणनीति का केंद्र रहा है। लेकिन अब अखिलेश ने इस राजनीतिक फामूलें में एक नया मोड़ दिया है। 'पी' की व्याख्या में पंडितों यानी ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी भले बहुत बड़ी न हो, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव हमेशा





संख्या से ज्यादा रहा है। गांव की चौपाल हो या शहर की राजनीतिक बैठक, कई इलाकों में ब्राह्मण मतदाता चुनावी माहौल और समीकरण दोनों पर असर डालता है।

बसपा ने 2007 में दलित-ब्राह्मण सामाजिक समीकरण को मजबूत करके सत्ता का रास्ता बनाया था। बाद में भाजपा के उभार और नरेंद्र मोदी की राजनीति के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ गए। अब अखिलेश उसी राजनीतिक जमीन में संभावनाएं तलाश रहे हैं।

त्रिशूल, शिव और समाजवाद का नया प्रयोग

अखिलेश यादव की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण बदलाव हिंदू प्रतीकों को लेकर दिखाई देता है। वह अब केवल पुराने समाजवादी ढांचे में सिमटकर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्हें मालूम

है कि 2027 का उत्तर प्रदेश 1990 के दशक का उत्तर प्रदेश नहीं है। इसलिए सपा प्रमुख हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से दूरी बनाने की बजाय उन्हें अपनी राजनीतिक भाषा का हिस्सा बना रहे हैं। सनातन धर्म की चर्चा, हनुमान चालीसा का पाठ, ब्राह्मणों तक पहुंच और धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी, यह सब एक व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा है। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर त्रिशूल और शिव स्तुति के बीच ब्राह्मणों तक पहुंचने का संदेश इसी नई राजनीति की तस्वीर है। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को भी इसी बड़े राजनीतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। संदेश साफ है कि सपा सामाजिक न्याय की बात भी करेगी और हिंदू समाज के साथ संवाद भी बनाएगी। वैसे यह भाजपा के हिंदुत्व की सीधी नकल नहीं, बल्कि अपने लिए अलग राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश है।

लेकिन असली पेंच भी यही है। उत्तर प्रदेश में समीकरण बनाना आसान है मगर उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाना मुश्किल है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में पीडीए का मूल आधार कमजोर नहीं हो। दूसरी चुनौती सपा की पुरानी राजनीतिक छवि है। भाजपा लगातार सपा के पिछले शासनकाल को कानून-व्यवस्था और कथित दबंग राजनीति के मुद्दे पर घेरती रही है। ऐसे में डिंपल यादव की बढ़ती भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका संयमित और सहज व्यक्तित्व सपा की छवि को नया आयाम दे सकता है। लेकिन यूपी की राजनीति में सिर्फ मुस्कुराहट से चुनाव नहीं जीते जाते। सवाल यह भी है कि क्या ब्राह्मण मतदाता वास्तव में भाजपा से दूर होंगे? क्या दलितों का बड़ा हिस्सा सपा की तरफ आएगा? क्या पिछड़ों के बीच पीडीए की पकड़ और मजबूत होगी? और क्या महिला मतदाता सपा को एक नए नजरिए से देखेंगे? सवाल यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलकर सचमुच एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार कर पाएगी?

देखा जाये तो अखिलेश के सामने एक और चुनौती विपक्षी राजनीति के भीतर भी है। अगर सपा एक तरफ सवर्णों को जोड़ने की कोशिश करे और दूसरी तरफ उसके राजनीतिक सहयोगियों की भाषा उसी वर्ग को असहज करे, तो समीकरण बनने से पहले ही बिगड़ सकते हैं। यूपी में राजनीति का यही असली गणित है कि एक जाति को जोड़ो तो दूसरी की नाराजगी का डर, एक वर्ग को साधो तो दूसरे को संदेश देने की चुनौती।

फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव 2027 के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी का नया संस्करण तैयार कर रहे हैं। उसमें पुराना समाजवाद है, नया पीडीए है, ब्राह्मणों के लिए जगह है, हिंदू प्रतीकों की स्वीकार्यता है और महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिंपल यादव जैसा एक अलग चेहरा भी है। यहां सवाल उठता है कि क्या 'शार्प' अखिलेश और 'सॉफ्ट' डिंपल का यह राजनीतिक संतुलन 2027 में सपा के लिए नई ताकत बनेगा? या फिर उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति के पुराने गठ्ठे इस नई साइकिल की रफ्तार रोक देंगे? जवाब 2027 देगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार साइकिल सिर्फ चलने नहीं, अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश में है।

मौत का इंतजार करती इमारतें और गहरी नींद सोता प्रशासन

यदि कोई इमारत नियमों के विरुद्ध बन रही थी तो निर्माण के दौरान संबंधित नगर निगम अधिकारी कहाँ थे? यदि वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थी तो फायर विभाग ने सुरक्षा का आकलन क्यों नहीं किया? बिजली और पानी के कनेक्शन किस आधार पर मिले? पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नजर उस भवन पर क्यों नहीं पड़ी?



दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में जो हृदयविदारक घटना घटित हुई है, वह केवल एक पाँच मंजिला इमारत के भरभराकर गिरने की घटना नहीं बल्कि राजधानी की उस व्यवस्था का ढहना है, जिसकी नींव नागरिकों की सुरक्षा, कानून के शासन और प्रशासनिक जवाबदेही पर टिकी होनी चाहिए थी। जिस इमारत में कुछ घंटे पहले तक देश के



अनिल वशिष्ठ

अलग-अलग हिस्सों से आए युवा अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे, देखते ही देखते वह ईंट,

सीमेंट और लोहे के मलबे में बदल गई। धूल का गुबार तो छंट जाएगा, मलबा भी हट जाएगा, सड़कें फिर सामान्य हो जाएंगी लेकिन उन परिवारों के जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है, वह कभी नहीं भर सकेगा। 'हॉस्टल डेज' नामक लड़कों के लिए बने पीजी की इस पाँच मंजिला इमारत में हादसे के वक्त कई छात्र अपने कमरों में थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है।



बताया जा रहा है कि इमारत लगभग 40-50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय बेसमेंट में मरम्मत तथा खुदाई का काम चल रहा था। यही तथ्य इस त्रासदी को और भयावह बना देता है।

सवाल केवल यह नहीं है कि इमारत क्यों गिरी बल्कि असली सवाल यह है कि इतनी पुरानी और संवेदनशील इमारत में बेसमेंट की खुदाई और निर्माण संबंधी गतिविधियां आखिर चल कैसे रही थी? हर बड़े भवन हादसे के बाद एक ही कहानी दोहराई जाती है। प्रशासन कहता है कि जांच होगी, कुछ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और कुछ दिनों बाद पूरा मामला फाइलों के नीचे दब जाता है।

फिर किसी दूसरे इलाके में कोई और इमारत गिरती है, कहीं आग लगती है, कोई बेसमेंट मौत का कुआं बन जाता है और हम फिर वही प्रश्न पूछते रह जाते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? सच तो यह है कि भारत के शहरों में कोई बहुमंजिला अवैध निर्माण रातों-रात खड़ा नहीं होता। जमीन का उपयोग बदलता है, नक्शा बनता है, निर्माण शुरू होता है, मंजिलें बढ़ती हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन मिलते हैं और अंततः उस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक विभागों और अधिकारियों की भूमिका होती है। ऐसे में यह कहना कि प्रशासन को कुछ पता ही नहीं था, जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान बहाना है।

देशभर से राजधानी में पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रोजगार तलाशने आने वाले हजारों युवा ऐसी इमारतों में रहते हैं, जहां कमरे छोटे हैं, गलियां संकरी हैं, सीढ़ियां संकरी हैं और सुरक्षा मानकों की स्थिति अक्सर संदिग्ध रहती है।

यदि कोई इमारत नियमों के विरुद्ध बन रही थी तो निर्माण के दौरान संबंधित नगर निगम अधिकारी कहां थे? यदि वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी तो फायर विभाग ने सुरक्षा का आकलन क्यों नहीं किया? बिजली और पानी के कनेक्शन किस आधार पर मिले? पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नजर उस भवन पर क्यों नहीं पड़ी? और यदि सब कुछ नियमों के अनुसार था तो फिर हादसा हुआ कैसे? यही वे प्रश्न हैं, जिनका जवाब केवल ठेकेदार या किसी छोटे कर्मचारी को दोषी ठहराकर नहीं दिया जा सकता। सत्य निकेतन की त्रासदी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दिल्ली में पीजी संस्कृति तेजी से बढ़ी है।

देशभर से राजधानी में पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रोजगार तलाशने आने वाले हजारों युवा ऐसी इमारतों में रहते हैं, जहां कमरे छोटे हैं, गलियां संकरी हैं, सीढ़ियां संकरी हैं और सुरक्षा मानकों की स्थिति अक्सर संदिग्ध रहती है। मकान मालिक के लिए कमरों की संख्या बढ़ाना कारोबार है लेकिन उस कमरे में रहने वाला छात्र अपने सपने लेकर वहां आता है। जब छह कमरों की अनुमति वाली इमारत में 25 से अधिक कमरे बना दिए जाते हैं, जब बेसमेंट को पार्किंग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब एक ही निकास मार्ग पर सैकड़ों लोगों की सुरक्षा निर्भर कर दी जाती है, तब यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं रहता, यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ बन जाता है।

दिल्ली में अतीत की त्रासदियां भी हमें बार-बार चेताती रही हैं। 1997 का उपहार सिनेमा अग्निकांड हो या हाल के वर्षों में सामने आए बेसमेंट, कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक इमारतों से जुड़े हादसे, हर घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। बंद दरवाजे, अवरुद्ध निकास, अवैध निर्माण, अग्निशमन उपकरणों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक उदासीनता बार-बार त्रासदियों की पृष्ठभूमि में दिखाई देती रही है। फिर भी व्यवस्था की स्मृति इतनी कमजोर है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर लौट

आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सस्पेंशन हमेशा छोटे कर्मचारी का ही क्यों होता है? यदि किसी इलाके में वर्षों तक अवैध निर्माण चलता रहा, यदि नियमों के विपरीत इमारतें खड़ी होती रही और उनमें पीजी, कोचिंग सेंटर, दुकानें या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलती रही तो उस पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसने इसे होने दिया। तत्कालीन अवैध निर्माण प्रभारी, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, जोनल स्तर के जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच क्यों न हो? यदि मिलीभगत प्रमाणित होती है तो कार्रवाई भी उसी अनुपात में कठोर क्यों न हो?

समस्या किसी एक इमारत की नहीं है। दिल्ली और देश के तमाम शहरों में हजारों ऐसी इमारतें हैं, जो बाहर से सामान्य दिखाई देती हैं लेकिन भीतर से मौत के जाल में बदल चुकी हैं। कहीं बेसमेंट में अवैध निर्माण है, कहीं बिना वेंटिलेशन के कोचिंग सेंटर, कहीं संकरी सीढ़ियां, कहीं बंद खिड़कियां, कहीं लोहे की ग्रिलें और कहीं एक ही प्रवेश-निकास द्वार। अग्निशमन उपकरण कई जगह केवल निरीक्षण के समय दिखाने के लिए रखे जाते हैं और आपातकालीन निकास कागजों पर मौजूद रहते हैं, वास्तविकता में नहीं। ऐसी स्थिति में हादसा होने पर दमकल की गाड़ियां भी संकरी गलियों में फंस जाती हैं। बचाव दल के पास पहुंचने का रास्ता नहीं होता और अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर कुछ ही मिनटों में एक इमारत कब्रिस्तान में बदल जाती है।

अब जरूरत केवल दोषी खोजने की नहीं, व्यवस्था बदलने की है। दिल्ली की सभी पुरानी बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। पीजी, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अनिवार्य जांच होनी चाहिए। फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध हो। अवैध निर्माण पर केवल जुमाना लगाकर उसे वैध बनाने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। गंभीर उल्लंघन वाली इमारतों को तत्काल सील और आवश्यकतानुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि जिम्मेदारी ऊपर तक जानी चाहिए। किसी दुर्घटना के बाद दो-चार छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देना प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, अक्सर जिम्मेदारी से बचने का

जमीन का उपयोग बदलता है, नक्शा बनता है, निर्माण शुरू होता है, मजिलें बढ़ती हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन मिलते हैं और अंततः उस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक विभागों और अधिकारियों की भूमिका होती है।

तरीका बन जाता है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, मिलीभगत या भ्रष्ट आचरण के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ी है तो उसके विरुद्ध कठोर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। पद जितना बड़ा हो, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। सत्य निकेतन का मलबा केवल ईंट-पत्थरों का ढेर नहीं है। उसके नीचे प्रशासनिक दावों की विश्वसनीयता, भवन सुरक्षा के नियमों

और नागरिकों के भरोसे की भी परीक्षा हो रही है। इस त्रासदी को ह्यहादसा कहकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा अपराध होगा। हादसा वह होता है, जिसे रोका न जा सके लेकिन जिस दुर्घटना की जमीन अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही से तैयार होती है, उसे केवल हादसा कहना सच्चाई को छोटा करना है। यदि इस बार भी जांच के नाम पर खानापूर्ति हुई, छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर बड़े जिम्मेदार बच निकले और कुछ लाख रुपये के मुआवजे को न्याय का विकल्प बना दिया गया तो अगली त्रासदी केवल समय की प्रतीक्षा करेगी। तब फिर कोई इमारत गिरेगी, कोई परिवार उजड़ेगा, कोई बच्चा मलबे में दबेगा और हम फिर पूछेंगे कि आखिर असली गुनहगार कौन है? जबकि सच हम सभी जानते होंगे। गुनहगार केवल वह व्यक्ति नहीं होगा, जिसने अवैध निर्माण किया बल्कि गुनहगार वह पूरा तंत्र होगा, जिसने उसे बनने दिया, चलने दिया और तब तक आंखें बंद रखी, जब तक मलबे ने चीखना शुरू नहीं कर दिया। अब समय चीख सुनने का नहीं, व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का है।





भावी संकट की पूर्व चेतावनी है नेपाल त्रासदी

आज संवाद या विचार का विषय यह नहीं रह गया है कि नेपाल त्रासदी में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है या कितनी जन-धन हानि हुई है अपितु यह हो जाता है कि इस तरह की त्रासदी से निपटने के लिए हम कहां तक तैयार है। सवाल यह भी है कि ऐसे हालात क्यों होते जा रहे हैं।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि दुनिया के देशों के लिए नेपाल त्रासदी को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। 2020 की कनाडा की रॉक स्लाइड और 2023 की सिक्किम में साउथ ल्होनक झील की ग्लेशियल फटने की घटना हमारे सामने हैं। यह कोई पहली या अंतिम घटनाएं नहीं हैं अपितु देखा जाए तो यह समय रहते प्रयास नहीं किये गये तो ऐसी घटनाओं की आवृत्ति जल्दी जल्दी और अतिविनाशकारी होगी, इससे नकारा नहीं जा सकता। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले सालों में जिस तरह से प्रकृति का विकराल रूप देखने को



मनोज शर्मा

मिल रहा है वह चाहे तूफानों के रूप में हो, चाहे जंगलों में लगती आग के कारण हो, ग्लेशियरों के पिघलने की हो, ग्लेशियलों के फटने की हो, भूकंपों की हो, बैमौसम आंधी बरसात की हो, अतिवृष्टि या अनावृष्टि की हो, मौसम चक्र में भले ही आंशिक

परिवर्तन की हो या समुद्री तूफानों की बढ़ती फ्रिक्वेंसी की हो बेहद गंभीर हो जाती है। वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की लगातार चेतावनी को नजरअंदाज करने का ही परिणाम है कि नेपाल जैसी त्रासदियां आम होती जा रही है। यह केवल नेपाल या इससे जुड़े क्षेत्र के लिए ही गंभीर हालात नहीं हैं अपितु अमेरिका, चीन, भारत सहित दुनिया के दस देश नेपाल जैसी त्रासदी के मुहाने पर खड़े हैं। ग्लेशियल के फटने या यों कहें कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोफ जैसे हालात कभी भी इनके दायरों में आने वाले देशों में हो सकते हैं। यह भी

सही है कि अभी तक भारत-नेपाल ही नहीं दुनिया के इस दायरों में आने वाला कोई भी देश इन आपदाओं से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सके हैं। जानकारों की मानें तो भारत, चीन, पाकिस्तान, पेरु के एक करोड़ 50 लाख लोग इनके दायरों में सीधे सीधे आ रहे हैं। यह वह लोग है जो इन ग्लेशियलों के एक किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरों में रह रहे हैं। आज ग्लोफ खतरों के दायरों में भारत, पाकिस्तान, कनाडा, पेरु, अमेरिका, चिली, इटली, नेपाल और कोलंबिया आए हुए हैं।

उत्तराखंड त्रासदी हमारे सामने हैं और उस त्रासदी के परिणाम सामने होने के बावजूद लगभग साल दर साल भूस्खलन के मामले हर सीजन में सामने आ रहे हैं। यह साफ हो जाना चाहिए कि प्रकृति से एक सीमा से अधिक खिलवाड़ किया जाता है तो विकृति का सामना हमें करना ही पड़ेगा। जीवनदायी यही प्रकृति अपने विकराल रूप में पलटवार करती है। ऐसे में समय के साथ सबक लेना जरूरी हो जाता है।

आज सारी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की बात तो की जाती है पर उस पर अमल पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो हालात यही रहे तो सदी के अंत तक समुद्र का जलस्तर दो मीटर तक बढ़ सकता है। तो दूसरी और अभी से समुद्र तटीय कई शहर डूबने की जद में आने की चेतावनियां दी जा रही है। नेपाल की हालिया त्रासदी का कारण ग्लेशियल का फटना माना जा रहा है। दरअसल ग्लेशियर और ग्लेशियल में हमें भेद करके चलना होगा। ग्लेशियर भौगोलिक संरचना होती है। यह पहाड़ों और ध्रुवों पर लंबे समय से जमा बर्फ



खण्ड होते हैं। यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जमे रहते हैं पर जलवायु परिवर्तन और तापमान के बढ़ने के कारण आज बड़ी मात्रा में ग्लेशियर के पिघलने की गति तेज होती जा रही है। दरअसल ग्लेशियरों के बड़े खण्डों के पिघल कर गिरने से ग्लेशियल झील बनती हैं। ग्लेशियल झील बन जाती है इसे हिमनदी झील भी कह सकते हैं। नेपाल की हालिया त्रासदी ग्लेशियल झील के फटने के कारण ही हुई है।

वैज्ञानिकों की माने तो ग्लेशियलों के निर्माण की गति में काफी तेजी आई है। यदि हम हिमालय क्षेत्र की ही बात करें तो सतलुज बेसिन में 2019 में 560 ग्लेशियल झीलें थी जो चार साल यानी की 2023 तक 1048 हो गई हैं। नेपाल त्रासदी ग्लेशियल लेक आदटबर्स्ट फ्लड यानी की ग्लोफ का परिणाम है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह ग्लेशियल झील के फटने का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक इन हालातों पर नजर नहीं रख रहे

हो बल्कि देखा जाए तो लीड्स विश्वविद्यालय के ग्लेशियल फ्लॉडिंग के विशेषज्ञ डॉ. जानाथन कारीविक पहले ही चेता चुके हैं। हमारे देश के ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के विशेषज्ञों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर हालात से रुबरु कराने के साथ ही टोस सुझाव भी दिए हैं। दरअसल एक सीमा से अधिक प्रकृति से छेड़छाड़ का ही परिणाम इस तरह की त्रासदियां होती हैं।

आज लाख चेतानों के बावजूद सतलुज बेसिन में बांधों के साथ साथ विद्युत परियोजनाओं सहित विकास परियोजनाओं का दखल बढ़ा है। एक सीमा से अधिक मानवीय दखल बढ़ी है। इससे तापमान में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होने के साथ ही अपशिष्ट भी फैल रहा है। दरअसल प्रकृति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ बढ़ रही है। एनडीएमए ने साफ साफ कहा है कि सतलुज बेसिन में नए निर्माण कार्या या नई परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले उनके परिणामों का भली प्रकार से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। परिणामों का आकलन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिए जाए। पर्यावरणीय परिणामों को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाए। यह भी देखा जाए कि ऐसे स्थानों में मानवीय दखल को एक सीमित दायरों तक ही रखा जाए। इसके साथ ही जलवायु व पर्यावरण विशेषज्ञों का दायित्व अधिक हो जाता है और आवश्यकता होने पर प्रकृति को बचाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैरसरकारी संगठनों को भी आगे आना होगा। आपदा प्रबंधन को भी ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा जिससे इस तरह की घटनाओं की समय रहते चेतावनी मिल सके ताकि कम से कम जन हानि को तो बचाया जा सके।



खाड़ी देशों में कार्यस्थल हादसों का गंभीर संकट हर सप्ताह औसतन तीन भारतीय श्रमिकों की मौत



मो. लईक टांडा

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता बनती जा रही है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 से 2025 के बीच विदेशों में कार्यस्थल दुर्घटनाओं के कारण 800 से अधिक भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें लगभग 55 प्रतिशत मौतें खाड़ी देशों में दर्ज की गईं, जो औसतन करीब तीन भारतीय श्रमिकों की प्रति सप्ताह मृत्यु के बराबर है।

कतर में हुए एक विस्फोट में 12 भारतीयों की मृत्यु की घटना ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, कार्यस्थल मानकों और नियोक्ताओं की जवाबदेही

को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया। ऐसी घटनाएं संकेत देती हैं कि विदेशों में रोजगार के अवसरों के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को समान प्राथमिकता देना आवश्यक है।

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में अधिक मौतें

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, तीन वर्षों की अवधि में सऊदी अरब में कार्यस्थल दुर्घटनाओं से 182 भारतीयों की मृत्यु हुई। यह संख्या औसतन प्रति सप्ताह एक से अधिक मृत्यु को दर्शाती है। संयुक्त अरब अमीरात में इसी अवधि के दौरान 128 भारतीय श्रमिकों की मौत दर्ज की गई। खाड़ी क्षेत्र के बाहर स्थित देशों से कार्यस्थल दुर्घटनाओं के अपेक्षाकृत कम मामले सामने आए हैं। प्रवासी श्रमिक संगठनों का मानना है कि कई देशों में कम संख्या का कारण बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के बजाय दुर्घटनाओं की अपर्याप्त

रिपोर्टिंग भी हो सकती है।

सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षण की कमी

प्रवासी भारतीयों से जुड़े संगठनों ने कार्यस्थल दुर्घटनाओं के पीछे कई गंभीर कारण बताए हैं। इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का अभाव, सुरक्षा नियमों का कमजोर अनुपालन, औद्योगिक स्थलों पर तकनीकी खराबियां तथा श्रमिकों को समुचित कौशल एवं सुरक्षा प्रशिक्षण न मिलना प्रमुख है।

निर्माण, खुदरा व्यापार, गोदाम, ऑटोमोबाइल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं। इनमें से कई क्षेत्र स्वभावतः उच्च जोखिम वाले हैं। इसके बावजूद श्रमिकों को हेलमेट, सुरक्षा जूते, दस्ताने, सुरक्षा बेल्ट और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

कई बार अत्यधिक गर्मी और असुविधा के

कारण श्रमिक स्वयं भी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते। कुछ श्रमिक संभावित खतरों और सुरक्षा मानकों से पूरी तरह परिचित नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में पर्याप्त प्रशिक्षण, नियमित सुरक्षा निरीक्षण और उपकरणों के इस्तेमाल की निगरानी अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

अत्यधिक तापमान से स्वास्थ्य पर प्रभाव

खाड़ी देशों में कई श्रमिक 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में काम करते हैं। काम समाप्त होने के बाद वे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले वातानुकूलित आवासों में लौटते हैं। शरीर को अचानक 20 से 25 डिग्री तक के तापमान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अत्यधिक गर्मी में लंबे समय तक काम करने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, थकावट और हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। यदि श्रमिकों को पर्याप्त विश्राम, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सहायता उपलब्ध न हो, तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है।

लंबे कार्य घंटे और वेतन में देरी

प्रवासी श्रमिकों से संबंधित शिकायतों में 12 घंटे तक की शिफ्ट, कई महीनों तक वेतन न मिलना, अनुचित कटौती और अत्यधिक कार्यभार जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। कुछ श्रमिकों को लगातार तीन महीने या उससे अधिक समय तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है।

खराब गुणवत्ता वाला भोजन, भीड़भाड़ वाले

आवास और अत्यधिक लंबे कार्य घंटे श्रमिकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रवासी संगठनों के अनुसार, आत्महत्या से जुड़े अनेक मामलों के पीछे आर्थिक तनाव, वेतन का भुगतान न होना, खराब आवास और कठिन कार्य परिस्थितियां महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

कुछ नियोक्ताओं पर कार्यस्थल दुर्घटनाओं से हुई मौतों को हीट अटैक या प्राकृतिक कारण बताने के आरोप भी लगे हैं। इससे मृतक श्रमिक के परिवार को बीमा और मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। कई मामलों में परिवारों को केवल सीमित बीमा राशि ही मिल पाती है।

भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं

विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई उपाय लागू किए गए हैं। इनमें 'प्रवासी भारतीय बीमा योजना' के अंतर्गत इमिग्रेशन चेक रिकवार्ड श्रेणी के श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का ई-केयर पोर्टल विदेश से पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए आवश्यक मंजूरी निर्धारित समय में उपलब्ध कराने की सुविधा देता है। यह पोर्टल दस्तावेजों की समयबद्ध स्वीकृति, स्वचालित सूचना और आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी में भी सहायता करता है।

भारतीय मिशनो के माध्यम से विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए सहायता केंद्र, श्रम प्रकोष्ठ, ओपन हाउस और दूरस्थ क्षेत्रों में कांसुलर शिविर संचालित किए जाते हैं। नई दिल्ली, दुबई, रियाद

और जेद्दा जैसे स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी भर्ती केवल राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से करने और ईसीआर पासपोर्ट धारकों की खाड़ी देशों में नियुक्ति 'ई-माइग्रेट' पोर्टल के जरिए कराने की व्यवस्था है।

सुरक्षा को कारोबारी जवाबदेही से जोड़ना आवश्यक

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की बढ़ती मांग देश के लिए रोजगार और विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसे श्रमिकों के जीवन और स्वास्थ्य की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भर्ती एजेंसियों, विदेशी नियोक्ताओं, ठेकेदारों और संबंधित सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

नियमित सुरक्षा ऑडिट, प्रमाणित प्रशिक्षण, पर्याप्त बीमा, समय पर वेतन भुगतान, सुरक्षित आवास और दुर्घटनाओं की पारदर्शी जांच को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर होने वाली प्रत्येक मृत्यु की स्वतंत्र जांच और पीड़ित परिवार को समयबद्ध मुआवजा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

प्रवासी श्रमिक केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि अपने परिवारों और देश की प्रगति में योगदान देने वाले नागरिक हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी के साथ एक महत्वपूर्ण मानवीय और व्यावसायिक दायित्व भी है।



7.8 फीसद की विकास दर



फिर आम आदमी की जेब क्यों खाली है ?

दे श की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 फीसद की वास्तविक विकास दर दर्ज की है। पहली नजर में यह आंकड़ा निश्चित रूप से प्रगतिशील दिखाई देता है। सरकार के लिए यह आर्थिक मजबूती का प्रमाण है और यह बताने का अवसर भी कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी गति बनाए हुए है। मगर किसी भी विकास का वास्तविक मूल्यांकन केवल विकास दर के आधार पर नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि इस विकास की गुणवत्ता क्या है, इसका लाभ किसे मिल रहा है और आम आदमी के जीवन में इसका कितना असर दिखाई दे रहा है।

जब तक समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचतीं, तब तक विकास को वास्तविक नहीं माना जा सकता। आर्थिक समृद्धि तब तक अधूरी है, जब तक वह लोगों की



सचिन तोमर

क्षमताओं में नहीं बदलती। विकास को सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंकड़े केवल आर्थिक उत्पादन को दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक विकास का संबंध मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता से है।

संकट का असर

अहम सवाल यह है कि पिछले वर्ष के आर्थिक आकार में कमी क्यों आई और इसका 7.8 फीसद की वर्तमान विकास दर पर कितना असर पड़ा? वर्ष 2011-12 के पुराने आधार वर्ष में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद 86.05 लाख करोड़ रुपए

था, जो वर्ष 2022-23 के नए आधार वर्ष में घटकर लगभग 80 लाख करोड़ रुपए रह गया। पुरानी और नई शृंखला की सीधी तुलना उचित नहीं है, लेकिन इतने बड़े बदलाव की वजह और वर्तमान विकास दर पर उसके प्रभाव को सरकार की ओर से स्पष्ट करने की जरूरत है।

पहली तिमाही अप्रैल से जून तक तीन माह की थी। पश्चिम एशिया का संकट फरवरी के अंत से शुरू हो चुका था, लेकिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि मई के मध्य और अंतिम सप्ताह में चार चरणों में हुई। यानी तिमाही का लगभग पहला डेढ़ महीना घरेलू ईंधन मूल्य वृद्धि के पूरे प्रभाव से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा और कीमत वृद्धि का दबाव बाद के हिस्से में आया। क्या यह सरकार की एक रणनीति नहीं थी कि कीमतों में वृद्धि का असर तिमाही के शुरूआती हिस्से पर कम दिखाई दे और उसका व्यापक प्रभाव बाद की अवधि में सामने आए?

देश में 31 अगस्त को जिस दिन 7.8 फीसद

की विकास दर सामने आई, उसी दिन सूचकांक 307 अंक यानी 0.40 फीसद और निफ्टी 0.39 फीसद नीचे बंद हुए। इसे केवल सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े की प्रतिक्रिया कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक बाजार, तेल और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर भी दबाव था। फिर भी मजबूत विकास दर के बावजूद बाजार में व्यापक उत्साह क्यों नहीं दिखाई दिया, यह प्रश्न बना हुआ है।

इसी के साथ रुपए में गिरावट का क्रम भी जारी है और वह लगभग 95 रुपए प्रति डालर के आसपास है। यदि अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है, तो हमारी मुद्रा अभी भी तेल की कीमतों, विदेशी पूंजी और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में क्यों रहती है? स्पष्ट है कि आर्थिक मजबूती केवल उत्पादन बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने की क्षमता भी है।

विकास की असली परीक्षा

आम आदमी के लिए 7.8 फीसद की विकास दर का सबसे सीधा परीक्षण उसकी रसोई और रोजमर्रा के खर्च में होता है। सरकारी कागजों में देश में औसत महंगाई दर 4.45 फीसद हो सकती है, लेकिन एक परिवार का बजट किसी औसत आंकड़े से नहीं चलता। जुलाई में खाद्य महंगाई 5.52 फीसद रही। अदरक, लहसुन और प्याज जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं में तेज वृद्धि दर्ज की गई।

सितंबर की शुरुआत में मुंबई क्षेत्र में दूध के दाम नौ रुपए प्रति लीटर बढ़े और सीएनजी तथा परिवहन किराए भी बढ़े। जयपुर में दूध के साथ पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद भी महंगे हुए। चीनी की कीमत में हाल में कुछ नरमी आई है, लेकिन उपभोक्ता तक राहत पहुंचने में समय लग रहा है। सीएनजी महंगी होने का असर आटो, टैक्सी और माल ढुलाई पर, दूध महंगा होने का असर दही, पनीर और मिठाई पर और ईंधन महंगा होने का असर लगभग हर वस्तु की ढुलाई पर पड़ता है। इसलिए एक परिवार के लिए महंगाई का अर्थ सूचकांक का फीसद नहीं, बल्कि महीने के अंत में बची रकम होती है।

विकास दर के इस आंकड़े का दूसरा बड़ा प्रश्न रोजगार से जुड़ा है। बीती जुलाई में बेरोजगारी दर 5.1 फीसद रही, जबकि श्रमबल भागीदारी दर 55.4 फीसद थी। केवल रोजगार की संख्या पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि क्या विकास युवाओं के



लिए पर्याप्त स्थायी और सम्मानजनक रोजगार पैदा कर रहा है।

यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, लेकिन संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार की गति कमजोर है और छोटे कारोबार लागत तथा मांग के दबाव में हैं, तो विकास की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत की बड़ी आबादी आज भी छोटे व्यापार, स्वरोजगार और अनौपचारिक गतिविधियों से जुड़ी है। इसलिए विकास का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि इन वर्गों की आय और कारोबार में क्या बदलाव आया।

वितरण में असमानता

देश की प्रति व्यक्ति आय अभी भी लगभग 2,700 डालर के आसपास है। दूसरी ओर, आय के वितरण में असमानता का प्रश्न भी गंभीर है। अगर राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा ऊपर के सीमित वर्ग के पास जा रहा है, तो ऊंची विकास दर अपने आप व्यापक आर्थिक समृद्धि का प्रमाण नहीं बन जाती। विकास तभी सार्थक है, जब उसकी पहुंच समाज के बड़े हिस्से तक हो और लोगों की क्रय शक्ति बढ़े।

जाहिर है, सरकार सकल घरेलू उत्पाद के इस आंकड़े को उपलब्धि के रूप में सामने रखेगी, विपक्ष इसकी कमियों और विश्वसनीयता पर

सवाल उठाएगा, अर्थशास्त्री गणना पद्धति पर बहस करेंगे तथा सामाजिक माध्यमों पर इसके पक्ष और विपक्ष में लंबी बहस चलेगी। यह सब लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन आम आदमी इन बहसों में बहुत देर तक नहीं उलझता। उसके लिए 7.8 फीसद केवल एक आंकड़ा है।

असल में वह देखता है कि उसकी आमदनी बढ़ी या नहीं, रोजगार मिला या नहीं, छोटा कारोबार चला या नहीं, घर का खर्च कितना बढ़ा और महीने के अंत में उसकी बचत कितनी रही। अगर उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, तो वह इस आंकड़े को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर नहीं देखेगा। आखिरकार अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि उसके आंकड़े आम आदमी के जीवन में कितने प्रभावी दिखाई देते हैं। उच्च जीडीपी यह नहीं बताती कि देश की संपत्ति का वितरण सभी लोगों के बीच समान रूप से हुआ है या वह कुछ ही लोगों के पास केंद्रित है। यह किसी नागरिक के स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे गैर-आर्थिक पहलुओं को भी नहीं दर्शाती है।

7.8 फीसद की विकास दर सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है, लेकिन यह सही मायने में तभी अर्थपूर्ण है, जब इसका असर देश के आम नागरिक की आय, रोजगार, बचत और क्रय शक्ति में दिखाई दे।

फ्री यूपीआई के दावे के बीच टगा रह गया आम आदमी

इस नए फ्रेमवर्क के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों से विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों और बाजारों तक में लोग इस कानून की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। जनता का स्पष्ट मानना है कि यह कानून उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर एक अदृश्य बेड़ी है।



अजीत शर्मा

मारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने और 'डिजिटल इंडिया' के सुनहरे सपने दिखाने वाली सरकार ने आखिरकार 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क के जरिए देश की जनता के भरोसे पर करारा प्रहार किया है। लंबे समय से यह ढोल पीटा जा रहा था कि यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस पूरी तरह मुफ्त है, सुरक्षित है और यह देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की ताकत है। लेकिन सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यह नया फैसला इस दावे की हवा निकालने के लिए काफी है। जनता आज टगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जिस डिजिटल व्यवस्था की आदत उन्हें डालकर कैशलेस होने के फायदे गिनाए गए थे, अब उसी व्यवस्था के पीछे छिपे टैक्स और चार्ज के कड़वे सच को सामने लाया जा रहा है।

सरकार चाहे जितने भी दावे करे कि यह चार्ज आम ग्राहकों को नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों को देना होगा, लेकिन आर्थिक मोर्चे की व्यावहारिक समझ रखने वाला कोई भी आम नागरिक यह बखूबी जानता है कि अंततः किसी भी टैक्स या फीस का बोझ घूम-फिरकर उपभोक्ता की जेब पर ही आकर गिरता है। यह नया ढांचा सीधे तौर पर देश के उस मध्यमवर्ग और नौकरीपेशा समाज के



साथ विश्वासघात है, जिसने सरकार के कहने पर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को पूरी तरह डिजिटल माध्यमों के सुपुर्द कर दिया था।

इस नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4% का टुअम्लगाने का फैसला किया गया है। सरकारी नीति निमाताओं ने बड़े ही शांति तरीके से यह आंकड़ा तैयार किया है ताकि पहली नजर में यह जनता को प्रभावित न करे। यह दलील दी जा रही है कि देश के 96 फीसदी मर्चेन्ट ट्रांजैक्शंस ₹2,000 से कम के होते हैं, इसलिए आम जनता सुरक्षित है। लेकिन यह पूरी तरह से एक सांख्यिकीय भ्रम है जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आज के इस महंगाई के दौर में ₹2,000 की रकम क्या अहमियत रखती है? एक मध्यमवर्गीय परिवार जब महीने का राशन खरीदने किसी सुपरमार्केट या किराना दुकान पर जाता है,

तो उसका बिल आसानी से ₹3,000 से ₹5,000 के पार चला जाता है। बच्चों की स्कूल की फीस, कोचिंग संस्थान के खर्च, बिजली और पानी के बड़े बिल, अस्पताल का खर्च, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी, या किसी शादी-व्याह के कपड़े खरीदना—ये सभी रोजमर्रा के ऐसे काम हैं जहां ट्रांजैक्शन की रकम ₹2,000 की इस कृत्रिम सीमा को पलक झपकते ही पार कर जाती है। ऐसे में यह कहना कि आम जनता इससे प्रभावित नहीं होगी, देश की बहुसंख्यक आबादी के जीवन स्तर और उनकी जरूरतों का क्रूर मजाक उड़ाने जैसा है। लोग और समाज

जनता के बीच इस कानून को लेकर जो सबसे बड़ा आक्रोश है, वह इस बात को लेकर है कि मर्चेन्ट्स पर लगाया गया यह चार्ज अंततः उन्हीं से वसूला जाएगा। कोई भी व्यापारी, चाहे वह छोटा

हो या बड़ा, अपनी जेब से 0.4% का घाटा नहीं सहेगा। बाजार का सीधा और शाश्वत नियम है कि जब भी किसी व्यवसाय की लागत बढ़ती है, तो वह उस लागत को अपने उत्पाद या सेवा की कीमत में जोड़ देता है। व्यापारी सीधे तौर पर भले ही यूपीआई पेमेंट करने पर आपसे अतिरिक्त पैसे न मांगें, लेकिन वे अपने सामानों के दाम में चुपके से 1 से 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर देंगे ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित रहे। इसका परिणाम यह होगा कि जो व्यक्ति नकद भुगतान करेगा, वह भी बिना वजह इस महंगाई की चपेट में आएगा और जो यूपीआई का इस्तेमाल करेगा, वह तो ठगा जाएगा ही। सरकार ने इस चालाकी से अपने राजस्व को बढ़ाने का रास्ता तो साफ कर लिया, लेकिन इसका सीधा खामियाजा उस जनता को भुगताना पड़ेगा जो पहले से ही बेकाबू महंगाई, बेरोजगारी और घटती क्रय शक्ति से जूझ रही है।

इस कानून के पीछे छुपा एक और बड़ा खतरा देश की बैंकिंग और डिजिटल साक्षरता के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करना है। भारत जैसे विकासशील देश में लोगों को नकद छोड़कर डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मोड़ना एक बहुत बड़ी सामाजिक और व्यावहारिक चुनौती थी। लोगों को बैंकों की लाइनों से बचाने और पारदर्शिता लाने के नाम पर सरकार ने खुद हर मंच से यूपीआई का प्रचार किया। रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े-बड़े मॉल तक क्यूआर कोड चिपकाए गए। जनता ने भी सरकार पर भरोसा किया और अपनी सदियों

पुरानी नकद लेन-देन की आदत को बदलकर जेब में बटुआ रखना बंद कर दिया। लेकिन अब, जब जनता पूरी तरह इस सिस्टम पर निर्भर हो चुकी है, तब सरकार ने अपनी असली नीयत दिखाते हुए इस पर शुल्क थोपना शुरू कर दिया है। यह नीति बिल्कुल वैसी ही है जैसी कोई निजी टेलीकॉम कंपनी पहले मुफ्त में सेवाएं देकर ग्राहकों को अपना आदी बनाती है और बाद में मनमाने दाम वसूलने लगती है। एक लोकतांत्रिक सरकार से जनहित की नीतियों की उम्मीद की जाती है, न कि किसी मुनाफाखोर कॉर्पोरेट घराने जैसी चालाकी की।

इस फैसले के लागू होने से बाजार में एक बार फिर से 'कैश इकोनॉमी' यानी नकद लेन-देन का चलन तेजी से बढ़ेगा, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक प्रतिगामी कदम होगा। जनता के मन में यह डर बैठ गया है कि आज ₹2,000 पर 0.4% का चार्ज लगा है, तो कल को सरकार इसे बढ़ाकर 1% कर देगी और सीमा को घटाकर ₹500 कर देगी। इस अविश्वास के कारण लोग अब फिर से बैंकों से नकद निकालकर अपने पास रखने को मजबूर होंगे। जब व्यापारी देखेंगे कि ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर उनका नुकसान हो रहा है, तो वे ग्राहकों को नकद भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या फिर यूपीआई पेमेंट लेने से साफ इंकार कर देंगे। इससे वह काला धन और समानांतर अर्थव्यवस्था फिर से सिर उठाएगी, जिसे खत्म करने का दावा सरकार अक्सर करती रही है। डिजिटल लेन-देन में आने वाली इस गिरावट के

लिए सीधे तौर पर सरकार की यह अदूरदर्शी और राजस्व-लोभी नीति जिम्मेदार होगी।

देश का बुद्धिजीवी वर्ग और जागरूक नागरिक इस बात से भी बेहद खफा हैं कि सरकार एक तरफ तो कॉर्पोरेट टैक्स में भारी छूट देती है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टा खाते में डाल देती है, लेकिन जब देश के आम नागरिकों की बात आती है, तो डिजिटल लेन-देन जैसी बुनियादी सुविधा पर भी टैक्स वसूलने के रास्ते तलाशने लगती है। ₹75,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम ₹300 की फीस तय करना इस बात का सबूत है कि सरकार को बड़े बिजनेसमैन की फिक्र है, लेकिन उस आम आदमी की कोई परवाह नहीं है जो अपनी गाड़ी कमाई का छोटा-छोटा हिस्सा जोड़कर जीवन यापन कर रहा है। सरकार का यह कदम देश के नागरिकों के वित्तीय अधिकारों का हनन है। जब देश की जनता पहले से ही हर सामान पर भारी-भरकम जीएसटी दे रही है, अपनी आय पर इनकम टैक्स चुका रही है, तो फिर अपने ही पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने या सामान खरीदने के डिजिटल माध्यम का उपयोग करने पर यह नया जुल्म क्यों ढाया जा रहा है?

इस नए फ्रेमवर्क के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों से विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों और बाजारों तक में लोग इस कानून की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। जनता का स्पष्ट मानना है कि यह कानून उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर एक अहश्य बेड़ी है। सरकार को यह समझना होगा कि डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं थी कि सरकार उससे कितना राजस्व कमा सकती है, बल्कि इस बात पर थी कि वह कितनी आसानी से और मुफ्त में देश के आम नागरिक को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ सकती है।

15 अक्टूबर से लागू होने जा रहा यह नया ढांचा यूपीआई की इस मूल भावना की हत्या है। जनता इस आर्थिक तानाशाही को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। यदि सरकार वास्तव में जनहितैषी होने का दावा करती है, तो उसे तुरंत इस जनविरोधी कानून को वापस लेना चाहिए और यूपीआई को बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा के हमेशा के लिए पूरी तरह मुफ्त रखने की लिखित गारंटी देनी चाहिए। अन्यथा, डिजिटल क्रांति का यह रथ बीच रास्ते में ही थककर रुक जाएगा और जनता का तंत्र से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा।



ब्रिक्स में भारत का बढ़ता कद, मजबूत होता 'ब्रांड मोदी'





“

भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता।





ब्रिक्स: वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच उभरता भारत, मजबूत होता मोदी ब्रांड

भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता।

दिल्ली में हुई ब्रिक्स शिखर बैठक को अगर केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मानकर देखा जाए तो उसकी असली राजनीतिक अहमियत समझ में नहीं आएगी। देखा जाये तो यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव, युद्ध, अविश्वास और बदलते शक्ति-संतुलन से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत ने जिस तरह अलग-अलग ध्रुवों के देशों को एक मंच पर बैठाया, संवाद के रास्ते खोले और मतभेदों के बावजूद सहयोग की जमीन तैयार की, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर सामने आई है।

ब्रिक्स की इस बैठक की सबसे बड़ी सफलता



ललित कुमार

यही रही कि भारत ने उन देशों के बीच भी संवाद की संभावना पैदा की, जिनके बीच गहरे मतभेद हैं। ईरान और खाड़ी के देशों के बीच बातचीत इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। पश्चिम एशिया लंबे समय से टकराव, अविश्वास और संघर्ष का मैदान बना हुआ है। ऐसे समय में दिल्ली का मंच बातचीत के लिए उपलब्ध होना अपने आप में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अलग-अलग पक्षों से संवाद करते हुए अपने लिए स्वतंत्र कूटनीतिक स्थान बना सकता है।

भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से

चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता। यही वह बिंदु है जहां मोदी की कूटनीति की ताकत दिखाई देती है। अमेरिका से संबंध भी कायम हैं, रूस के साथ रिश्ते भी बने हुए हैं, चीन से संवाद भी हो रहा है और पश्चिम एशिया के अलग-अलग देशों के साथ भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। यानी भारत किसी एक शक्ति के पीछे चलने के बजाय अपनी शर्तों पर संबंधों का संतुलन साध रहा है।

यही सफलता उस राजनीतिक नैरेटिव को भी कमजोर करती है, जिसमें बार-बार यह सवाल उठाया जाता रहा कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मक्का समझौता कर लिया, दूसरे देशों के साथ अपने समीकरण बना लिए और क्षेत्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ीं तो क्या भारत की विदेश नीति असफल हो गई? विदेश नीति को केवल पड़ोस की तत्काल घटनाओं से मापना

पश्चिम एशिया लंबे समय से टकराव, अविश्वास और संघर्ष का मैदान बना हुआ है। ऐसे समय में दिल्ली का मंच बातचीत के लिए उपलब्ध होना अपने आप में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अलग-अलग पक्षों से संवाद करते हुए अपने लिए स्वतंत्र कूटनीतिक स्थान बना सकता है।



वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देना है। असली सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को किस नजर से देख रही हैं और संकट के समय कितने देश भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की बैठक ने इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे दिया है।

यहां प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग की तस्वीरें जिस तरह वैश्विक स्तर पर चर्चा में आई हैं, उनका राजनीतिक संदेश तस्वीर से कहीं बड़ा है। यह तस्वीर बताती है कि भारत का नेतृत्व एक साथ दुनिया की अलग-अलग शक्तियों के साथ संवाद करने की स्थिति में है। पश्चिमी देशों के लिए भी यह संदेश महत्वपूर्ण है कि भारत को नजरअंदाज करके वैश्विक राजनीति की कोई बड़ी रणनीति पूरी नहीं हो सकती।

इसका घरेलू राजनीतिक असर भी कम नहीं होगा। भाजपा लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत वैश्विक छवि को अपनी राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करती रही है। ब्रिक्स की दिल्ली बैठक उस पूंजी को और मजबूत करने का अवसर देती है। विपक्ष यदि यह कहता है कि सरकार की विदेश नीति कमजोर पड़ गई है, तो भाजपा के पास दिल्ली में जुटे वैश्विक नेताओं, भारत की मध्यस्थ भूमिका और अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ संवाद को सामने रखने का मजबूत राजनीतिक आधार तैयार हो गया है।

सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मिली यह कूटनीतिक सफलता केवल एक शिखर सम्मेलन की सफलता बनकर नहीं रहने वाली। इसका सीधा और दीर्घकालिक लाभ भारत की सामरिक स्थिति को मिल सकता है। रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप, ईरान और खाड़ी देशों जैसे अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ एक साथ संवाद कायम रखने की मोदी की क्षमता ने यह संदेश दिया है कि भारत किसी

दबाव या धड़े की राजनीति में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ संबंध तय करने की स्थिति में है। इसका असर आने वाले समय में व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक सहयोग और भारत की वैश्विक हैसियत, हर मोर्चे पर दिखाई दे सकता है।

साथ ही इस सफलता का एक घरेलू राजनीतिक पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रमाण के रूप में जनता

के सामने रख सकती है। विपक्ष यदि विदेश नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाता है, तो भाजपा के पास दिल्ली में एक साथ जुटे विश्व के बड़े नेताओं और मोदी की सक्रिय कूटनीतिक भूमिका को सामने रखने का अवसर होगा। यानी ब्रिक्स की सफलता सिर्फ दिल्ली की कूटनीतिक मेज पर मोदी की जीत नहीं है; यह आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार और मोदी की नेतृत्व छवि को और मजबूत करने वाली उपलब्धि भी बन सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता ने घरेलू राजनीति में ब्रांड मोदी को और मजबूत कर दिया है।



ब्रिक्स में भारत की नई कूटनीति: वैश्विक शक्ति-संतुलन बदलने की कोशिश कितनी कामयाब



नितिन शर्मा

देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है, जब विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट और व्यापारिक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

इसमें दोराय नहीं कि सहयोग और स्थिरता का निर्माण विभिन्न देशों के बीच संवाद, विश्वास एवं साझेदारी को मजबूत करता है। आज वैश्विक तनाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन, जलवायु संकट और सुरक्षा चुनौतियों के बीच विश्व शांति, संतुलित विकास और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन में आम सहमति से जारी घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट नजर आई कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बदलती वैश्विक व्यवस्था में अधिक प्रभावी भूमिका देने की जरूरत है।

ब्रिक्स देश आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाकर वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, सदस्य देशों के राष्ट्रीय हित, राजनीतिक मतभेद और आर्थिक असमानताएं भी एक चुनौती हैं, मगर साझा सहमति से यह समूह विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय, प्रतिनिधिमूलक और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

इसके संकेत ब्रिक्स के 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में नजर आते हैं, जिसमें वैश्विक शांति, संघर्षों का कूटनीतिक समाधान, आतंकवाद के विरुद्ध



सहयोग, बाधा रहित व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी एवं डिजिटल सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इस घोषणापत्र को ब्रिक्स और भारत की सफलता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सदस्य देशों ने मतभेदों के बीच साझा सहमति कायम की और वैश्विक शांति, बहुपक्षवाद, आर्थिक सहयोग, विकास तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर सामूहिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

भारत के सामने भी अब इन कूटनीतिक अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने की चुनौती है। रूस, चीन, ईरान और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ बने संवाद को आर्थिक, रणनीतिक एवं तकनीकी सहयोग से आगे बढ़ाना भारत के हित में होगा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी

जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन की भारत यात्रा महज एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी नहीं थी। यह ऐसे समय में हुआ, जब दुनिया शक्ति-संघर्ष, युद्ध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और पश्चिम एशिया में तनाव के दौर से गुजर रही है।

ऐसे में रूस, चीन, ईरान और वैश्विक दक्षिण के प्रमुख प्रतिनिधियों का भारत आकर एकजुटता दिखाना नई दिल्ली की कूटनीतिक क्षमता और बढ़ती स्वीकार्यता का महत्वपूर्ण संकेत है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी संदेश है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर पुतिन की उपस्थिति रूस-भारत संबंधों की निरंतरता का प्रतीक बनी है। शी जिनपिंग की मौजूदगी भारत-चीन संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जबकि पेजेशिकयन की भागीदारी पश्चिम एशिया, ऊर्जा और संपर्क मार्गों के संदर्भ में भारत

की भूमिका के महत्व को दर्शाती है।

ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान की सक्रिय भागीदारी अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। इससे अमेरिका को भी यह आभास हुआ है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग नहीं है और उभरती शक्तियों के साथ उसके संबंध महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इस सम्मेलन ने भारत को रूस, चीन और ईरान के साथ उच्चस्तरीय संवाद का अवसर दिया है। बहुपक्षीय बातचीत से जहां रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, वहीं चीन के साथ सीमा पर शांति कायम रखते हुए व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ईरान के साथ चाबहार, ऊर्जा, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी है। ऐसे में भारत आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों को कमजोर किए बिना सभी शक्ति केंद्रों के साथ संवाद रखने वाली स्वतंत्र कूटनीति पर आगे बढ़ सकता है।

ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता, विशाल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और वैश्विक दक्षिण में बढ़ती स्वीकार्यता इसकी ताकत है। विस्तारित ब्रिक्स विश्व की बड़ी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम

नहीं हैं। हालांकि, ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्दाओं में व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की दिशा में प्रयास जारी है, मगर डॉलर आधारित व्यवस्था का मजबूत विकल्प अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रिक्स का प्रभाव आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में तो दिखाई देता है, लेकिन सामूहिक रणनीतिक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका अभी विकासशील अवस्था में है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार, व्यापार, जलवायु, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर ब्रिक्स अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। आने वाले समय में उसकी सफलता इस बात से तय होगी कि सदस्य देश अपने आर्थिक सामर्थ्य को कितनी प्रभावी सामूहिक कार्यवाई में बदल पाते हैं।

आयोजन और कूटनीतिक मेजबानी की दृष्टि से ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए बड़ी सफलता रहा, मगर इस दौरान डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देने, स्थानीय मुद्दाओं में व्यापार को गति देने और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने जैसे मसलों पर अपेक्षित ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। इससे यह प्रश्न भी उठता है कि क्या ब्रिक्स आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाया है? चीन का बढ़ता प्रभाव कई सदस्य देशों के लिए चिंता का विषय है।

परस्पर व्यापार में गहरी असमानताएं और भारत-चीन संबंधों की जटिलताएं ब्रिक्स की सामूहिक क्षमता को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर, ब्रिक्स के अनेक देशों के अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। ऐसी विविध परिस्थितियां ब्रिक्स के सामने साझा दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय की चुनौती बढ़ाती हैं।

ब्रिक्स के सामने एक बुनियादी प्रश्न यह भी है कि यह समान भागीदारी वाला बहुपक्षीय मंच बनेगा या चीन का आर्थिक प्रभाव इस पर हावी रहेगा। रणनीतिक रूप से रूस की नजदीकियां चीन के साथ हैं। ईरान के चीन से गहरे संबंध हैं, जबकि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश अपनी अलग आर्थिक प्राथमिकताएं रखते हैं।

दूसरी ओर, भारत ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाने के बजाय इसे व्यावहारिक सहयोग का मंच बनाए रखना चाहता है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत ने साझा मुद्दा जैसे मुद्दे को आगे बढ़ाने के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्दाओं और भुगतान प्रणालियों में सहयोग पर जोर दिया। यदि ब्रिक्स हर तरह से संतुलन को कायम रखता है, तो वह बहुध्रुवीय विश्व का प्रभावी मंच बन सकता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर उसके भीतर अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता।



मोदी होना आसान नहीं



संजीव कुमार



कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसकी छवि बनाते हैं। भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म से सब प्राप्त किया जा सकता है। गुजरात के निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी के

व्यापक विस्तार की कहानी भी ऐसी ही है। मोदी ने अपने और अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। उनके चिंतन के केंद्र में आम आदमी प्रमुखता से है। संभवतः वे पंडित दीनदयाल जी की उस उक्ति को धरती पर लाने का उपक्रम कर रहे हैं, जिसमें अंतिम छोर पर निवास करने वाले व्यक्ति का उत्थान छुपा हुआ है। तभी तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। इतना ही नहीं, वे अपने आपको प्रधान सेवक मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जनता

के साथ जुड़ाव बनाने वाला यह कथन अपने जीवन में समाहित कर लिया है। ऐसा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी होना आसान नहीं है।

किसी व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होने वाला पद बड़ा हो सकता है, लेकिन पद से बड़ा होता है उसका व्यक्तित्व। कुर्सी शक्ति दे सकती है, किंतु उस शक्ति को धैर्य, संयम और संकल्प के साथ साधना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इसी कारण अलग दिखाई देता है। उनके समर्थकों के लिए वे संघर्ष से निकली उस यात्रा के प्रतीक हैं, जिसमें अभावों से उठकर व्यक्ति देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचता है। सच कहें तो मोदी होना आसान नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वर्तमान राजनीतिक चुनौतियां नई नहीं हैं। सत्ता के गलियारों में जितनी प्रशंसा मिलती है, उतनी ही तीखी आलोचना भी उनका पीछा करती है। राजनीतिक प्रहारों की निरंतरता किसी भी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले सकती है। लेकिन मोदी की राजनीतिक शैली की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि वे अपने समर्थकों की अपेक्षाओं और विरोधियों के आक्रोश के बीच अपना संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। राजनीति में विरोध आवश्यक है। लोकतंत्र में सत्ता से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। नीतियों की सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक असहमति जब व्यक्तिगत कटुता का रूप लेती है, तब लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती है। ऐसे वातावरण में भी स्वयं को संयमित रखना किसी नेता के लिए सामान्य बात नहीं। आज की राजनीति केवल मोदी का समर्थन या विरोध पर ही केंद्रित हो गई है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि मोदी का प्रचार विपक्षी दलों ने अधिक किया है।

मोदी की राजनीतिक यात्रा का सबसे प्रेरक पक्ष उनका संघर्ष है। एक सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की कहानी भारतीय लोकतंत्र की उस शक्ति को रेखांकित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी अंतिम सीमा तय नहीं करती। अभावों में पला व्यक्ति भी अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर राष्ट्र के नेतृत्व तक पहुंच सकता है। यही मोदी की कहानी का

सबसे बड़ा संदेश है।

मोदी के व्यक्तित्व की चर्चा करते समय उनके परिवार और व्यक्तिगत जीवन का पक्ष भी सामने आता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका परिवार सत्ता के केंद्र में दिखाई नहीं देता। सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए पारिवारिक जीवन को राजनीतिक लाभ से दूर रखने की उनकी छवि उनके समर्थकों के लिए विशेष महत्व रखती है। भारतीय राजनीति में जहां परिवारवाद लंबे समय से बहस का विषय रहा है, वहां मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करती है।

मोदी की कहानी केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। आज विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति पहले से अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार हुआ है। वैश्विक मंचों पर भारत की शक्तिशाली भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाना उस बदलते भारत का संकेत है, जो अपनी क्षमता, अपने हितों और अपनी सभ्यता की पहचान के साथ विश्व समुदाय के सामने खड़ा होना चाहते हैं। वे जब विदेश दौरा करते हैं, तब वे भारतीय मूल के नागरिकों से अवश्य मिलते हैं। इस दौरान भारतीय मूल के व्यक्तियों के चेहरे बहुत ही प्रफुल्लित दिखाई देते हैं। वे सभी मोदी को एक सफल नायक की श्रेणी में देखते हैं। अपनेपन का यह भाव मोदी के स्वभाव का ही परिणाम है। राजनीति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए विदेश यात्राओं या कूटनीतिक मुलाकातों का विषय नहीं है। यह उस आत्मविश्वास का विषय है, जिसके साथ भारत आज विश्व समुदाय से संवाद कर रहा है।

एक समय था जब दुनिया के अनेक शक्तिशाली देश भारत को मुख्यतः एक विकासशील राष्ट्र के रूप में देखते थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी युवा शक्ति, उसकी तकनीकी क्षमता, उसका विशाल बाजार और उसकी सामरिक भूमिका विश्व की चर्चा का

महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परिवर्तन का पूरा श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत की इस वैश्विक प्रस्तुति को निश्चित रूप से एक विशिष्ट राजनीतिक दिशा दी है। और यही मोदी की विशेषता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वे भारत को केवल वर्तमान के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जितना मुखर है, उतना ही व्यक्तिगत जीवन में सादगी और अनुशासन की छवि से जुड़ा हुआ भी है। सार्वजनिक जीवन में निरंतर सक्रियता, दैनिक रूप से लंबे कार्य घंटे, देश-विदेश की यात्राएं और करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का भार, प्रधानमंत्री का जीवन किसी सामान्य नौकरी की तरह नहीं होता। प्रत्येक निर्णय के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय परिणाम जुड़े होते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री होना केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। यह हर दिन स्वयं को कटघरे में खड़ा करना भी है। एक ओर समर्थकों की अपेक्षाएं, दूसरी ओर विरोधियों के

सवाल। एक ओर देश की आकांक्षाएं, दूसरी ओर विश्व की निगाहें। एक ओर वर्तमान की चुनौतियां, दूसरी ओर भविष्य के भारत की जिम्मेदारी। इन सबके बीच संतुलन बनाना ही नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा है।

नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन को देखने का सबसे सार्थक तरीका यही है कि हम उनके संघर्ष, संकल्प और नेतृत्व की यात्रा को समझें। मतभेद लोकतंत्र की सुंदरता हैं। उनके भीतर एक ऐसा नेतृत्व दिखाई देता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। उनके आलोचक चाहे उनके निर्णयों से सहमत हों या नहीं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित चेहरों में से एक हैं। उनकी यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचना कठिन है, लेकिन उस ऊंचाई पर टिके रहकर निरंतर आगे बढ़ते रहना उससे भी कठिन है। मोदी होना इसलिए आसान नहीं है। मोदी होने के निहितार्थ यही हैं संघर्ष को शक्ति में बदलना। आलोचना को सहने का धैर्य रखना। सफलता के बीच जमीन से जुड़े रहना। भारत की आकांक्षाओं को विश्व के सामने आत्मविश्वास से रखना। और सबसे बढ़कर, स्वयं से बड़ी किसी राष्ट्रीय आकांक्षा के लिए निरंतर काम करते रहना।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें देखने का एक दृष्टिकोण यह भी है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला व्यक्ति किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में असाधारण राजनीतिक पहचान बना सकता है। राजनीति के निर्णयों का मूल्यांकन इतिहास करेगा। नीतियों की समीक्षा समय करेगा। उपलब्धियों और कमियों का आकलन आने वाली पीढ़ियां करेंगी। लेकिन संघर्ष की कहानी अपनी जगह रहती है।

और नरेंद्र मोदी की कहानी का यही सबसे बड़ा भाव है, एक साधारण शुरुआत से असाधारण शिखर तक की यात्रा। इसलिए जन्मदिन के इस अवसर पर एक वाक्य सहज ही मन में उभरता है कि मोदी होना आसान नहीं।



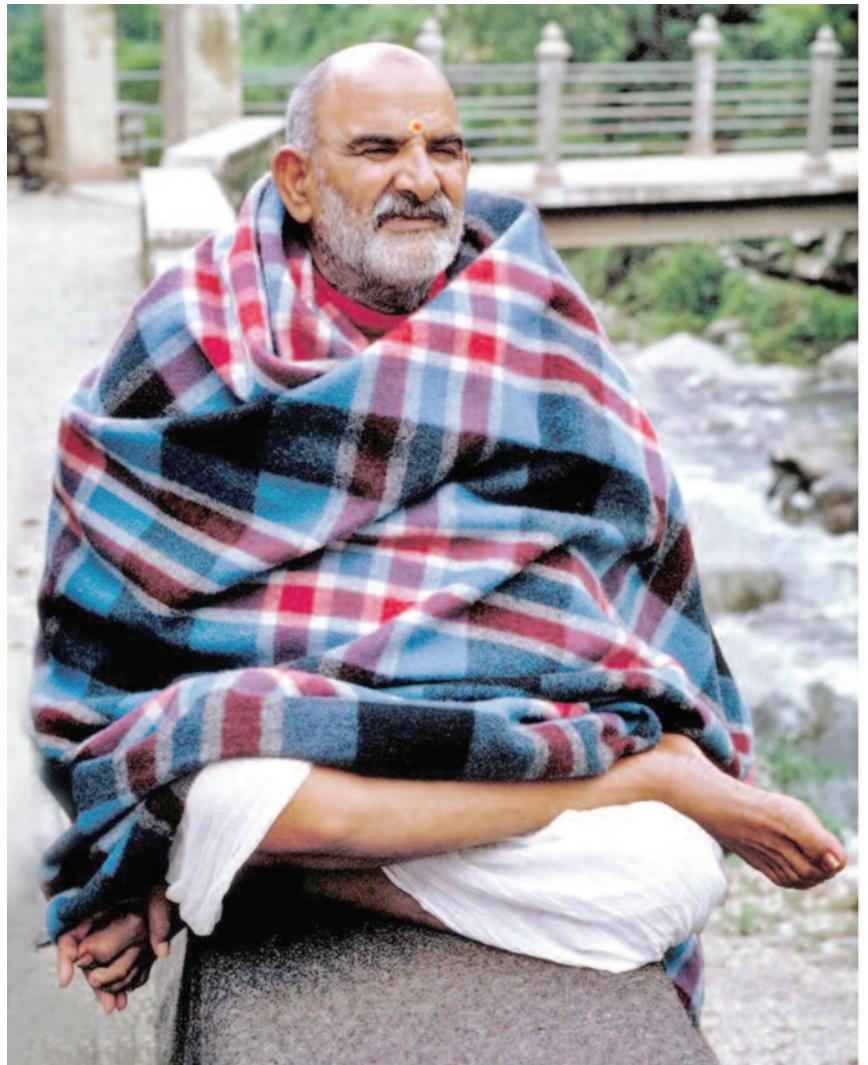
महासमाधि दिवस पर यूपी पर्यटन की बड़ी पहल नीब करोरी बाबा के नाम से बना नया आध्यात्मिक सर्किट

- ▶ नीब करोरी बाबा की विरासत को बड़ा सम्मान, यूपीएसटीडीसी ने शुरू किए 5 प्रकार के खास टूर पैकेज
- ▶ दिल्ली-लखनऊ से चलेंगे बाबा नीब करोरी के विशेष टूर...2, 3 और 5 दिन के पैकेज शुरू
- ▶ ₹12.93 करोड़ से संवरेंगे बाबा नीब करोरी से जुड़े स्थल, पर्यटन विभाग ने तैयार किया आध्यात्मिक ट्रेल
- ▶ नीब करोरी बाबा की विरासत को संरक्षित कर देश-दुनिया तक पहुंचा रही सरकार: जयवीर सिंह



राजेंद्र सिंह

श्रद्धेय संत नीब करोरी बाबा के 'महासमाधि दिवस' पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने उनकी आध्यात्मिक विरासत को देश-दुनिया के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नीब करोरी बाबा के जीवन और विरासत से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन का नया सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए 'बाबा नीब करोरी' के पांच विशेष



टूर पैकेज भी शुरू किए हैं। इसके साथ ही फिरोजाबाद और फरुखाबाद में पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 12.93 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद के

अकबरपुर को बाबा नीब करोरी की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है। फेज-1 के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास पर 8.65 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2.22

करोड़ रुपये की फेज-2 परियोजना का 60 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अकबरपुर में 55.44 लाख रुपये की ग्रामीण पर्यटन परियोजना भी जल्द शुरू की जाएगी। वहीं फरुखाबाद स्थित नीब करोरी आश्रम के विकास पर 1.51 करोड़ रुपये की परियोजना पूरी हो चुकी है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य बाबा से जुड़े स्थलों को बेहतर सुविधाओं के साथ एक व्यवस्थित आध्यात्मिक पर्यटन अनुभव में बदलना है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नीब करोरी बाबा का 'महासमाधि दिवस' ऐसे संत को याद करने का अवसर है, जिनका आस्था, सादगी और सेवा का संदेश आज भी भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया वर्ष 2017 से पहले बाबा के जीवन और विरासत से जुड़े स्थलों की पर्यटन क्षमता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब उनकी विरासत को संरक्षित करने और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। पर्यटन परियोजनाओं, बेहतर सुविधाओं और विशेष रूप से तैयार पर्यटन अनुभवों के माध्यम से बाबा की विरासत को जीवंत रखने के साथ प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के नए अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं।

अकबरपुर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यहां बहुदेशीय सभागार, सांस्कृतिक ब्लॉक और बाबा के जीवन एवं आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित आधुनिक प्रदर्शनी हॉल बनाया जा रहा है। इसके



अलावा डाइनिंग हॉल, 50 लोगों की क्षमता वाली कैफेटेरिया, रसोई, शौचालय और करीब 60 लोगों के ठहरने के लिए डॉरमेट्री की सुविधा विकसित की जा रही है। फेज-2 में गार्ड रूम, सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं और पत्थर के रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत प्रवेश द्वार, साइनेज, म्यूरल वॉल और पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। फरुखाबाद के नीब करोरी आश्रम में भी यात्रियों के ठहरने के लिए भवन, मुख्य द्वार और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं।

बाबा की आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े प्रमुख स्थलों को अब 'नीब करोरी बाबा सर्किट' के रूप में जोड़ा जा रहा है। इस सर्किट में वृंदावन स्थित समाधि मंदिर शामिल है, जहां वर्ष 1973 में बाबा ने महासमाधि ली थी। इसके साथ फिरोजाबाद का

अकबरपुर गांव, फरुखाबाद का नीब करोरी बाबा आश्रम धाम मंदिर और लखनऊ का प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर भी सर्किट का हिस्सा हैं। मान्यता है कि फरुखाबाद स्थित आश्रम में बाबा ने भूमिगत गुफा में करीब 12 वर्ष साधना की थी। इस तरह जन्मस्थली से लेकर समाधि स्थल तक बाबा की आध्यात्मिक यात्रा को एक ही पर्यटन मार्ग में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

महासमाधि दिवस को खास बनाते हुए यूपीएसटीडीसी ने 'बाबा नीब करोरी' के पांच विशेष टूर पैकेज * शुरू किए हैं। जिसमें 5 दिन, 3 दिन और 2 दिन की यात्राएं शामिल हैं। पर्यटकों की मांग के आधार पर इन पैकेजों का संचालन दिल्ली और लखनऊ से किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा को आसान बनाना है। अपर मुख्य सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक अमृत अभिजात ने बताया कि नया 'नीब करोरी बाबा सर्किट' उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आध्यात्मिक पर्यटन सर्किटों में एक महत्वपूर्ण नया आयाम जोड़ेगा। बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों को एक साथ जोड़ने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इन स्थानों तक पहुंच आसान होगी और उन्हें बाबा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि महासमाधि दिवस पर शुरू किए गए विशेष टूर पैकेज इस पहल को और उपयोगी बनाएंगे तथा बाबा की विरासत को भारत के साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।



बदलते मौसम चक्र में राहत की उम्मीद, अल नीनो के असर को संतुलित कर सकती है अटलांटिक नीना



अरुण शर्मा

प्रकृति ने अपने भीतर न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपा रखे हैं, जिनकी परतें विज्ञान धीरे-धीरे खोल रहा है। जब भी कोई नई प्राकृतिक घटना सामने आती है, मनुष्य को अपने सीमित ज्ञान का एहसास होता है। भू-विज्ञान, मौसम विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ जानना, समझना और सीखना बाकी है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच मौसम की अनिश्चितता ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई है। ऐसे समय में जब अल नीनो के कारण कमजोर और अनियमित मानसून की आशंका जताई जा रही थी कि इसी बीच अटलांटिक नीना की सक्रियता ने कुछ राहत की उम्मीद जगाई।

अटलांटिक नीनो और नीना अपेक्षाकृत नई समझी जाने वाली जलवायु घटनाएं हैं। प्रारंभ में इनके अस्तित्व ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। इनके स्वरूप और प्रभावों का अध्ययन करने पर पता चला कि इनका संबंध वैश्विक जलवायु और बढ़ते तापमान से भी है। हालांकि इनके नाम प्रशांत महासागर में होने वाली 'अल-नीनो' और 'ला-नीना' से मिलते-जुलते हैं, लेकिन दोनों को एक ही मानना उचित नहीं है।

अटलांटिक नीनो और नीना भू-मध्यरेखीय अटलांटिक महासागर में होने वाली परस्पर विपरीत जलवायु घटनाएं हैं। अटलांटिक नीनो की स्थिति तब बनती है, जब भू-मध्यरेखीय अटलांटिक का समुद्री जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके विपरीत, अटलांटिक नीना के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। अटलांटिक नीनो के समय पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ती हैं, जबकि अटलांटिक नीना में ये हवाएं अपेक्षाकृत मजबूत हो जाती हैं। तेज हवाएं समुद्र की गहराई से ठंडे पानी को ऊपर लाने में मदद करती हैं। इन दोनों



घटनाओं का वर्षा और मौसम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अटलांटिक नीनो उष्णकटिबंधीय अटलांटिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, अटलांटिक नीना की स्थिति में वर्षा का स्वरूप बदल जाता है। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में कम वर्षा और गिनी की खाड़ी के आसपास अपेक्षाकृत अधिक वर्षा जैसी स्थितियों के पीछे समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण में होने वाले बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वैज्ञानिकों के लिए यह तथ्य विशेष रूप से अहम रहा कि वैश्विक ताप लगातार बढ़ने के बावजूद कभी-कभी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर के भू-मध्यरेखीय क्षेत्रों में एक साथ ठंडक दिखाई

देती है। ऐसी स्थिति का संबंध ला नीना और अटलांटिक नीना जैसी घटनाओं से हो सकता है। ये दोनों घटनाएं समुद्र और वायुमंडल के बीच होने वाली जटिल पारस्परिक क्रिया को समझने में महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। जुलाई और अगस्त 2024 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में लंबे समय से जारी असाधारण गर्मी के बीच भू-मध्यरेखीय अटलांटिक क्षेत्र में ठंडक दिखाई दी।

यह स्थिति इसलिए भी उल्लेखनीय थी, क्योंकि जून के प्रारंभ में समुद्र की सतह का तापमान काफी अधिक था। इसके बाद अटलांटिक नीना के विकसित होने के संकेत मिलने लगे। इसी अवधि में पूर्वी प्रशांत महासागर में भू-मध्यरेखा के निकट समुद्री जल भी ठंडा हो रहा था। प्रशांत क्षेत्र में ला नीना के

विकसित होने की संभावना सामान्य तौर पर अक्तूबर या नवंबर के आसपास मानी जा रही थी, लेकिन इसके संकेत अपेक्षाकृत पहले दिखाई देने लगे।

इन घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक वायुमंडलीय परिसंचरण के कई संकेतकों का अध्ययन करते हैं। इनमें 'वेग विभव' भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से यह समझने में सहायता मिलती है कि बड़े क्षेत्र में वायु कहां ऊपर उठ रही है और कहां नीचे उतर रही है। नीचे उतरती वायु सामान्यतः वातावरण को स्थिर बनाती है। इससे बादलों का निर्माण और उष्णकटिबंधीय तूफानों की गतिविधि कम हो सकती है। इसके विपरीत, ऊपर उठती वायु अधिक बादल और वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय तूफानी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। समुद्र की सतह का तापमान और वायुमंडलीय दबाव इन प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़े होते हैं।

पिछले चार दशकों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह संकेत मिला है कि अटलांटिक नीना की सक्रियता के दौरान अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब चक्रवातों की संख्या और उनके तट तक पहुंचने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत, अटलांटिक नीनो अफ्रीकी पूर्वी तरंग गतिविधि और निम्नस्तरीय चक्रवाती परिसंचरण को मजबूत करता है। ऐसी परिस्थितियां केप वर्डे द्वीपसमूह के आसपास गहरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शक्तिशाली तूफानों के विकसित होने की संभावना

बढ़ाती हैं। अटलांटिक नीना का प्रभाव केवल तत्काल मौसम तक सीमित नहीं रहता। पिछले चार दशकों के अध्ययन यह संकेत देते हैं कि गर्मियों में अटलांटिक की समुद्री स्थितियां आगे आने वाली सर्दियों के मौसम को भी प्रभावित कर सकती हैं। ग्रीष्मकालीन अटलांटिक नीनो के बाद कनाडा और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर निम्न वायुदाब की स्थिति बनने की संभावना देखी गई है। इससे ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली जेट धाराओं की तीव्रता प्रभावित हो सकती है।

जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तेज और संकरी वायु धाराएं हैं। सामान्यतः ये लगभग 20,000 से 50,000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं और इनकी गति 120 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो सकती है। ध्रुवीय ठंडी हवा और विषुवतीय गर्म हवा के बीच तापमान तथा वायुदाब में अंतर इनके निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। जेट धाराएं ठंडी और गर्म वायु राशियों को अलग रखने के साथ-साथ मौसम प्रणालियों, तूफानों और चक्रवातों के निर्माण को भी प्रभावित करती हैं।

अब सबसे अहम प्रश्न यह है कि सक्रिय अटलांटिक नीना आने वाले समय में क्या प्रभाव डाल सकती है। समुद्र की सतह के तापमान में

गिरावट से विकसित यह जलवायु स्थिति प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि मानसून निश्चित रूप से सामान्य या अत्यधिक अच्छा होगा, लेकिन ये परिस्थितियां कमजोर मानसून की आशंका को कुछ कम कर सकती हैं।

भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का अभाव बना रहता है। ऐसे में अटलांटिक महासागर की गतिविधियों का अध्ययन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अटलांटिक नीना की सक्रियता यदि अपेक्षित रूप से प्रभावी रहती है, तो वह ला नीना के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकती है।

परिणामस्वरूप भारत में मानसून की सक्रियता बढ़ने और वर्षा में तेजी की संभावना बन सकती है। समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण, जेट धाराएं, वैश्विक तापमान और अन्य अनेक कारक मिलकर मानसून और तूफानों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए अटलांटिक नीना को मानसून के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यदि इसकी सक्रियता बनी रहती है, तो अल नीनो के प्रभाव के बावजूद वर्षा की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद की जा सकती है।



बिखरते रिश्तों के बीच अकेला पड़ता बचपन

आज के बच्चे कम उम्र में ही घर के बदलते माहौल को समझने लगे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि एकल परिवारों में उनके पास अक्सर कोई मजबूत भावनात्मक सहारा नहीं होता।



हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने बिखरते पारिवारिक परिवेश और बच्चों के भावनात्मक संसार को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि आइफोन की चाहत पूरी न होने पर 18 वर्षीय युवक ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस जांच में घटना के पीछे कहीं अधिक गंभीर और जटिल पारिवारिक परिस्थितियां सामने आईं। जांच के अनुसार, युवक अपने माता-पिता के बीच बढ़ती दूरियों और पारिवारिक संबंधों की उलझनों से मानसिक रूप से परेशान था।

बताया गया कि पारिवारिक विवादों से व्यथित युवक पहाड़ी पर खड़ा होकर माता-पिता को अपनी जान देने की धमकी दे रहा था। उसे बचाने के लिए पुलिस, अग्निशमन दल और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। लंबे समय तक समझाइश, मिन्नतों और भावनात्मक अपीलों का दौर चलता रहा, लेकिन मानसिक रूप से बेहद तनावग्रस्त युवक



राजेंद्र सिंह

पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। उसे बचाने के प्रयास में उसके पिता का भी संतुलन बिगड़ गया और दोनों करीब 300 फीट नीचे जा गिरे। इस भयावह दृश्य के बीच वहां मौजूद मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत उस भावनात्मक संकट का प्रतीक है, जो परिवारों के भीतर चुपचाप आकार ले रहा है।

आज के बच्चे कम उम्र में ही घर के बदलते माहौल को समझने लगे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि एकल परिवारों में उनके पास अक्सर कोई मजबूत भावनात्मक सहारा नहीं होता। कहीं माता-पिता के अलगाव की वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया बच्चों को असुरक्षित बना देती है, तो कहीं

एक ही छत के नीचे रहते हुए रिश्तों में आई खामोश दरारें उनके मन में भय पैदा करती रहती हैं।

घर का तनावपूर्ण वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा असर डालता है। माता-पिता के बीच रोज-रोज होने वाले झगड़े, कटुता और आरोप-प्रत्यारोप बच्चों को भीतर से अस्थिर कर देते हैं। ऐसे बच्चे कई बार अपने घर के माहौल की तुलना मित्रों और रिश्तेदारों के घरों से करने लगते हैं। जब उन्हें दूसरे परिवारों में सहजता और अपनापन दिखाई देता है, तो उनके भीतर शिकायतों और सवालियों का एक संसार जन्म लेने लगता है, लेकिन अक्सर वे अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाते।

नकारात्मक व्यवहार और पारिवारिक कलह के बीच बड़े होते बच्चों के मन में अनेक प्रश्न दस्तक देने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि माता-पिता के बीच रोज-रोज की नाराजगी और तलखी का कारण क्या है। उनके सामने सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। कई बार माता-पिता अनजाने में बच्चों को

अपने विवादों का हिस्सा बना लेते हैं और उनसे दूसरे अभिभावक के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की अपेक्षा करते हैं। यह स्थिति बच्चे के मन पर असहनीय दबाव डाल सकती है।

कई परिवारों में बच्चों को माता-पिता के हिंसक व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। पहले से तनाव और असुरक्षा से जूझ रहा बालमन ऐसे व्यवहार से आहत होता है। संवेदनात्मक स्तर पर अकेले पड़ते बच्चों में से कुछ घर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ गंभीर आत्मघाती विचारों की ओर बढ़ रहे हैं। पारिवारिक विवादों से जुड़े अध्ययनों में संकेत मिला है कि बच्चों के घर छोड़ने के पीछे बड़ों का अपमानजनक व्यवहार और घर का असुरक्षित वातावरण खास कारणों में शामिल होता है।

वास्तव में, बच्चे चाहे छोटे हों या किशोरावस्था में पहुंच चुके हों, उनकी दुनिया माता-पिता से गहराई से जुड़ी होती है। खुशी की चहक हो या सुरक्षा का एहसास, बालमन अपनी अनुभूतियों को परिवार के साथे में ही आकार देता है। इसके विपरीत, लंबे समय तक माता-पिता के संबंधों में नकारात्मकता देखने वाले बच्चों का मन और मस्तिष्क इस उहापोह से अछूता नहीं रह सकता। उनका विश्वास टूटने लगता है, उम्मीदें बिखरने लगती हैं और भय तथा असुरक्षा धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।

सूचनाओं और तकनीक की भरमार वाले इस दौर में बच्चे पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं। वे घर के तनाव, आर्थिक समस्याओं, रिश्तों की दूरी और माता-पिता के व्यवहार को समझते और महसूस करते हैं। इसलिए अभिभावकों को भी बच्चों के मनोभावों को समझने के लिए अधिक संवेदनशील होना होगा। परिवार का तनावपूर्ण माहौल बच्चे के विकास के हर मोर्चे पर जोखिम पैदा कर सकता है। बच्चे निराशावादी हो सकते हैं और अपने मन की बातें साझा करना बंद कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध भी पारिवारिक अस्थिरता के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर संकेत करते हैं। अस्थिर पारिवारिक वातावरण में बड़े होने वाले बच्चों में चिंता, तनाव और कम आत्मसम्मान जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। माता-पिता की उदासी, घर में लगातार विवाद, अपमानजनक व्यवहार और असुरक्षित वातावरण उनके विकास को प्रभावित करते हैं। कई बच्चे मानवीय संबंधों, विश्वास और संवाद की स्वस्थ समझ विकसित करने में कठिनाई महसूस करते हैं

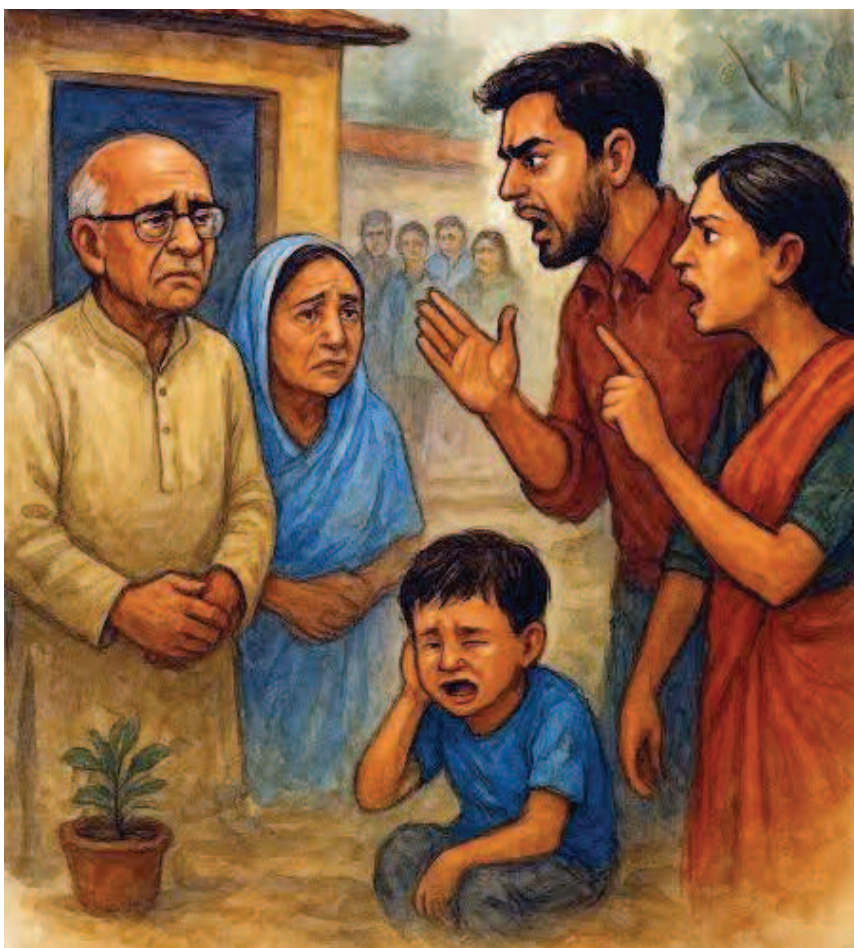
और अधूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े होते हैं।

स्पष्ट है कि माता-पिता का मनमुटाव बच्चों के मन का वातावरण भी बदल देता है। अभिभावकों का अलगाव हो या साथ रहते हुए लगातार चलने वाली कटुता, दोनों ही स्थितियां बच्चों के जीवन को अशांति और उलझनों से भर सकती हैं। माता-पिता के बीच असहमतियों और नकारात्मक टिप्पणियों का प्रतिदिन सामना करने वाले बच्चों की जिंदगी कई बार दिशाहीन हो जाती है।

यह समस्या केवल आम परिवारों तक सीमित नहीं है। चर्चित और संपन्न परिवारों में भी रिश्तों का बिखराव बच्चों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि न्यायालय भी वैवाहिक विवादों में बच्चों के हित और उनकी भावनात्मक स्थिरता को विशेष महत्व देते रहे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान जुड़वां बच्चियों ने माता-पिता के झगड़ों और आपसी हिंसा को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। बच्चियों की बातों ने यह स्पष्ट कर दिया कि माता-पिता के विवादों की सबसे बड़ी कीमत

अक्सर बच्चे चुकाते हैं।

ऐसे में जरूरी है कि अभिभावक केवल तलाक या अलगाव की प्रक्रिया के दौरान ही नहीं, बल्कि साथ रहते हुए भी अपने संबंधों में संयम और सहजता बनाए रखने का प्रयास करें। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों के सामने अपमान, हिंसा और कटुता का प्रदर्शन उनके मन पर स्थायी घाव छोड़ सकता है। अगर रिश्ते बचाना संभव न हो, तो भी बच्चों के हित में सम्मानजनक संवाद और सहयोगपूर्ण सह-अभिभावकत्व आवश्यक है। बच्चे अक्सर शब्दों से अधिक अपने माता-पिता के व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए बड़ों का संवेदनशील, संयमित और संतुलित व्यवहार ही बच्चों के मनोविश्व को सुरक्षित रख सकता है। रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बच्चों का बचपन मतभेदों की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। आखिर एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और संवादपूर्ण परिवार ही उस मजबूत पीढ़ी की नींव रख सकता है, जो जीवन की चुनौतियों से टूटने के बजाय उनका सामना करना सीखे।



जीवन की राह में ज्ञान का दीप जलाते हैं शिक्षक

आज के दौर में अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता अक्सर यह रहती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में अक्ल आए, प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाए और आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारी बने। निसंदेह जीवन में सफलता, उत्कृष्ट शिक्षा और व्यावसायिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं।



विश्वभर में लगभग सभी महापुरुषों ने शिक्षकों को राष्ट्रनिर्माता की संज्ञा दी है। गुरु रूपी इन्हीं शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को 'शिक्षक दिवस' मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा दिन है, जब छात्र अपने शिक्षकों अर्थात् गुरुओं को उपहार देते हैं। पहले जहां गुरुकुल परम्परा हुआ करती थी और उस समय जीवन की व्यावहारिक शिक्षाएं इन्हीं गुरुकुल में गुरु दिया करते थे, आज नए जमाने में गुरुओं का वही अहम कार्य शिक्षक पूरा कर रहे हैं, जो छात्रों के सच्चे मार्गदर्शक बनकर उन्हें स्कूल से लेकर कॉलेज तक वह शिक्षा देते हैं, जो उन्हें जीवन में बुलाईयों तक पहुंचाने में सहायक बनती है। आज भले ही शिक्षा प्राप्त करने या ज्ञानोपार्जन



मनोज शर्मा

के लिए अनेक तकनीकी साधन सुलभ हैं किन्तु एक अच्छे शिक्षक की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक अच्छा शिल्पकार किसी भी पत्थर को तराशकर उसे खूबसूरत रूप दे सकता है और एक कुम्हार गीली मिट्टी को सही आकार प्रदान कर सही आकार के खूबसूरत बर्तन बनाता है, समाज में वही भूमिका एक शिक्षक अदा करता है, इसीलिए शिक्षक को समाज के असली

शिल्पकार का भी दर्जा दिया जाता है। इतिहास ऐसे शिक्षकों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी शिक्षा से अनेक लोगों के जीवन की दिशा ही बदल दी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर भारत में प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

13 मई 1962 को राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने और उसी वर्ष उनके कुछ छात्र उनका जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से उनके पास गए तो उन्होंने उन छात्रों को परामर्श दिया कि उनके जन्मदिन को अध्यापन के प्रति उनके समर्पण के लिए 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाए और इस प्रकार 5

सितम्बर 1962 से ही देश में यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 15 सितम्बर 1888 को एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मे डा. राधाकृष्णन ने अपने जीवनकाल के 40 वर्ष एक आदर्श शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिए। मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दर्शन शास्त्र पढ़ाया। 1931 में किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की किन्तु उन्होंने देश की आजादी के बाद अपने नाम के साथ 'सर' लगाना बंद कर दिया। राधाकृष्णन 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे और 1954 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। 1962 में ब्रिटिश अकादमी का सदस्य बनने पर उन्हें गोल्डन स्पर, इंग्लैंड के 'ऑर्डर ऑफ मैरिट' तथा 1975 में मरणोपरांत अमेरिकी सरकार द्वारा 'टेम्पलटन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। डा. राधाकृष्णन एक महान् दार्शनिक और आदर्श शिक्षक होने के साथ-साथ राजनीति में भी प्रवीण थे।

दर्शन शास्त्र जैसे गंभीर विषय को भी डा. राधाकृष्णन अपनी अद्भुत शैली से बेहद सरल और रोचक बना देते थे। जिस विषय का वे अध्यापन करते थे, पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। डा. राधाकृष्णन अपने व्याख्यानों के साथ-साथ विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से छात्रों को उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में समाहित करने के लिए प्रेरित कर उनका बेहतर मार्गदर्शन भी करते थे। उनका कहना था कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि शिक्षक के बिना इस दुनिया में हम सभी अधूरे हैं। शिक्षक ही हैं, जो देश के भविष्य के वास्तविक आकृतिकार हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। राधाकृष्णन का कहना था कि हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए, जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। उनका कथन स्पष्ट था कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा और शिक्षा को एक मिशन के रूप में नहीं अपनाएगा, तब तक अच्छी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती।

आज के दौर में अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता अक्सर यह रहती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आए, प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाए और आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक

भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं
द्वितीय राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली
राधाकृष्णन के जन्मदिवस के
अवसर पर भारत में प्रतिवर्ष 5
सितम्बर को शिक्षकों के प्रति सम्मान
प्रकट करने के उद्देश्य से शिक्षक
दिवस मनाया जाता है।

या प्रशासनिक अधिकारी बने। निसंदेह जीवन में सफलता, उत्कृष्ट शिक्षा और व्यावसायिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं लेकिन केवल ऊंचे पद और बड़ी डिग्रियां किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाती।

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चे को सफल बनाने के साथ-साथ उसे एक संवेदनशील, विवेकशील, जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना भी होना चाहिए। यदि ज्ञान के साथ संस्कार, चरित्र और मानवीय मूल्यों का विकास नहीं हुआ तो ऐसी

शिक्षा अधूरी ही मानी जाएगी। हर बच्चे को नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही और गलत के बीच अंतर कर सके तथा अपने विवेक से बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बने।

शिक्षा ऐसी हो, जो केवल प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की क्षमता न दे बल्कि सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन, ईमानदारी, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करे। यही गुण आगे चलकर परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा-दर्शन भी इसी व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित था। उनका विश्वास था कि सही शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए शिक्षक दिवस केवल शिक्षकों के सम्मान का अवसर नहीं बल्कि शिक्षा के उद्देश्य पर आत्ममंथन का दिन भी है। उनके आदर्शों, शिक्षाओं और जीवन-मूल्यों को अपनाकर ही हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जो ज्ञानवान होने के साथ संस्कारित, संवेदनशील और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान दे।



कृष्ण का जन्म ही अनुष्ठान है, कृष्ण का जीवन ही उत्सव है

कृष्ण के जन्म का अनुष्ठान है। इसके बाद की सभी घटनाओं का बहुत अर्थ नहीं, वह सब उनके सामान्य जीवन का हिस्सा है। कृष्ण का जीवन ही उत्सव है, वही प्रेक्षणीय है, वही लीला है, वही उत्सव के योग्य है।



भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष, चहुँओर अँधियारे का साम्राज्य है, घनघोर वृष्टि से पृथ्वी जलमग्न हो रही है, आकाश को घेरे काले बादलों ने अँधियारे को और भी गहरा कर दिया है, बीच-बीच में कड़कती बिजली इन्द्र के व्रज-सी गगन को भेदती पृथ्वी को प्रकम्पित कर जाती है, उसपर मथुरा में कंस का अँधियारा भरा साम्राज्य, अत्याचारों की पराकाष्ठा से राज्य त्राहि कर रहा है, कठोर कारागार में बंद देवकी और वासुदेव के सात पुत्रों को शैशवावस्था में ही निर्दयता से मारा जा चुका है, ऐसे में भाद्रपद, कृष्ण



अरुण मिश्रा

पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को माँ देवकी के गर्भ से प्रभु प्रकट होते हैं !!

अँधियारा जितना गहन होगा, प्रकाश की दीप्ति उतनी ही प्रकट होकर आभामय होगी। नकार की गहनता सकार को श्रेयस रूप में प्रकट होने के लिए

भूमि तैयार करती है ! वरना क्या संभव था कि अत्याचार इतनी सीमाओं को लाँघता ! वह बहुत पहले अस्तित्वविहीन किया जा सकता था। मगर जब कृष्ण जैसे विराट अवतार को प्रकट होना हो, जब कन्हैया स्वयं बालक रूप धरने वाले हों, जब पृथ्वी पर सौ सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट होना हो तो अँधियारे को तो गहन होना ही होगा। इसलिए कृष्ण के जन्म के समय इतने अँधियारे और भयावह समय का रूपक प्रकृति द्वारा रचा गया है। चूँकि मनुष्य, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर किसी के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार, फैलाया जाने वाला

अँधेरा उतना गहन नहीं हो सकता जितने को मिटाने के लिए कृष्ण जैसी आभा की आवश्यकता हो, इसलिए कृष्ण के जन्म के समय गहन अँधेरे के असंख्य रूपक प्रकृति ने रचे हैं। यँ भी कृष्ण की विराट आभा के समक्ष कोई भी अँधियारा अर्थहीन हो होगा, कोई भी अति सामान्य ही होगी। और वह हुआ भी। कृष्ण के प्रकट होते ही, कारागार के द्वार खुल गए, देवकी वासुदेव के बंधन टूट गए, समय का रथ ठहर गया, संसार प्रकाशमान हो गया !

कृष्ण के लिए यह सब बेहद सामान्य है। कृष्ण जन्म के साथ से ही यह सूचना देते आ रहे हैं कि वे असाधारण हैं। वे जन्म के साथ ही अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। उनका जीवन चमत्कारों से भरा है। वे स्वयं को साधारण दिखाने का प्रयास भी नहीं करते। बल्कि यह कहें कि उनकी प्रभा इतनी द्युतिमान है कि वह लाख प्रच्छन्नताओं के बाद भी प्रकट होती है, उसे रोका नहीं जा सकता। वह समय और काल की बाध्यताओं को नहीं स्वीकारती।

कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट है कि वह साधारण घटनाओं के दायरे में नहीं समाता। इसलिए कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरित होने का उद्देश्य सामान्य नहीं है। कृष्ण कंस को मारने के लिए प्रकट नहीं होते, वह उनके लिए बेहद सहल था और न ही कंस उनके जन्म का उद्देश्य है। जिस प्रकार विष्णु के अन्य अवतारों का उद्देश्य किसी आसुरी शक्ति को समाप्त करना था, इस तरह का कोई उद्देश्य कृष्ण के जीवन में नहीं है। इसलिए कंस को मारने में किसी प्रकार की विशेष वीरता और महानता का संदर्भ नहीं है और न ही कृष्ण को कंस के युति विलोम में देखा जाता है। कृष्ण-कंस के मध्य किसी भीषण युद्ध की भी चर्चा नहीं है। कृष्ण अपने 1 महीने की उम्र में ही पूतना को मार देते हैं, 3 महीने में शकटासुर, 1 वर्ष में तृणावर्त, 2 वर्ष में वत्सासुर, 4 वर्ष में बकासुर, 5 वर्ष में अघासुर, 5 वर्ष में ही कालिया मर्दन, 6 वर्ष में धेनुकासुर, 7 वर्ष में गोवर्धन उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ते तथा 11 वर्ष में कंस का वध कर देते हैं। इन सारे वृहत कार्यों को करने में उन्हें किसी प्रकार की विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हँसते-खेलते सामान्य जीवन की घटनाओं के साथ वे इन आसुरी शक्तियों से भी निपटते जाते हैं। इसमें किसी अतिरिक्त आयोजन की आवश्यकता तक नहीं पड़ती। उनकी क्षमता अनंत है, अनिर्वचनीय है, वे ही ब्रह्म हैं और वे ही जगत। वे ही सुर भी हैं, असुर भी, वे ही आदि भी और अंत भी। परंतु एक ही साथ वे जितने अलौकिक हैं उतने

ही लौकिक भी। वे जिस तरह बाल रूप धर लीलाएँ रचते हैं वह अद्भुत है। उनका जीवन किसी उद्देश्य को योजित नहीं है, वह तो जीवन की संपूर्णता को समर्पित है। वह जब बालक के स्वरूप में हैं तो सम्पूर्ण रूप से बालक हैं। उतने ही निर्मल, उतने ही नटखट, उतने ही सरल, उतने ही हठी। बालक के व्यक्तित्व का कोई हिस्सा उनसे अछूता नहीं है। इसलिए सभी उनसे इतना प्रेम करते हैं।

कृष्ण के प्रति प्रेम, उनके ऐश्वर्य की उपासना नहीं है, बल्कि कृष्ण की कोई भी उपासना नहीं है, कृष्ण के प्रति केवल प्रेम है। इसलिए कृष्ण को लेकर किसी तरह का अनुष्ठान निरर्थक होगा, उनके लिए तो प्रेम ही समग्र अनुष्ठान है। गोपियाँ उनके चमत्कारों और ईश्वरत्व पर आकर्षित नहीं होतीं, वे उनकी मासूमियत पर मोहित हैं, उनकी निर्मलता ने उन्हें आकृष्ट कर लिया है, उनकी सादगी और उनकी समग्रता उन्हें खींचती है। आज भी स्त्रियाँ कृष्ण के प्रेम में वैरागी हो सकती हैं, उनके लिए संसार त्याग सकती हैं, लोक-लाज ताज सकती हैं, मीरा राजमहलों को छोड़ वन-वन भटक सकती है, कृष्ण के प्रेम में दीवाना हुआ जा सकता है। स्त्रियाँ शब्द का उल्लेख इसलिए किया कि स्त्रियाँ ही अब भी प्रेम को परख सकती हैं, पुरुष में अभी भी गणित हावी है। इसलिए स्त्रियाँ कृष्ण के प्रेम में पड़ें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि कृष्ण प्रेम की ही मूरत हैं। कृष्ण को प्रेम से ही पाया जा सकता है, कृष्ण ही प्रेम हैं। कृष्ण इकलौते ऐसे अवतार हैं जो हमेशा बाल्यावस्था में हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पृथ्वी के नियमों को त्याग दिया, वे भी समय के साथ बढ़ते हैं, परन्तु बाल्यावस्था में ही वे उतने समग्र हैं कि हमें

उससे आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। उतने ही प्यारे, उतने सुन्दर, उतने हठी। और वे भी बाल्यावस्था में प्रेम को उतना ही प्रेम समर्पित करते हैं। कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल पर दुनिया के सारे नियम लागू होते हैं, उन्हें भूख लगती है, उन्हें ठंड लगती है, उन्हें बुखार होता है, बस उनकी उम्र नहीं बढ़ती। कितना प्यारा रूपक है यह। वे हमेशा बालक हैं। उनका बालपन समग्र है। उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। वे उस स्वरूप में प्रेम पर रीझ जाते हैं जिस स्वरूप में हम प्रेम को लुटा सकते हैं। उन्हें भूख लगती है कहते हुए भी दुनियावी नियमों के अर्थ में गणितीय तात्पर्य तो यही है कि वे खाते नहीं परन्तु उन्हें भूख लगती है यह सोचकर हमारे मन में जो उनके प्रति प्रेम का भाव उमड़ा यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्हें बुखार लगी होगी यह सोचकर बेचैन हो जाना ही तो प्रेम है। प्रियतम के विछोह को याद कर रो लेना ही तो प्रेम है। यही प्रेम का सार है। कृष्ण इसी प्रेम में हैं, कृष्ण प्रेम से हैं। कृष्ण का इस पृथ्वी को लेकर कोई उद्देश्य नहीं है। उनकी आभा इतनी विराट है कि इस पृथ्वी के लिए उनका कोई भी उद्देश्य नगण्य ही होगा। इसलिए उनके जीवन को हम लीला कहते हैं। वे किसी दैत्य का वध करने हेतु इस पृथ्वी पर आएँ, इतनी छोटी अपेक्षा हम भी उनसे नहीं रखते। वे हमारा प्रेम स्वीकारें यह बहुत है, वे हमारे माखन चुराएँ और हम उन्हें बाँधें, यह काफी है। वे हमें दीवाना बना जाएँ, हम वन-वन घूम उनके लिए तड़पें यह पर्याप्त है। वे हमेशा हमारे पालने में बच्चे बनकर झूलें, हम उन्हें बच्चों की तरह खिलाएँ, उनके कपड़े बदलें, उनका खयाल रख सकें, उन्हें चूम सकें यह बहुत है।



बेजान बालों के लिए बेहद असरदार है राइस वॉटर रिस

प्रदूषण और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे बाल बेजान नजर आने लगते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए फर्मेंटेड राइस वॉटर एक बेहद कारगर और प्राकृतिक उपाय साबित होता है। सही तरीके से राइस वॉटर रिस करने से न केवल बालों का टूटना कम होता है, बल्कि प्राकृतिक चमक भी लौट आती है।

प्रदूषण, धूल-मिट्टी, बदलता मौसम और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बालों की नमी कहीं खो जाती है, जिस कारण बाल बेजान और रुखे नजर आते हैं। गौरतलब है कि बेजान बालों के कारण आपकी खूबसूरती में कमी आती है। इस समस्या से बचने के लिए ज्यादातर महिलाएं महंगे-महंगे हेयर स्पा या फिर कंडीशनर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होगा। अगर आप चावल के पानी यानी राइस वॉटर का इस्तेमाल करेंगे, तो बेजान बालों की समस्या झड़ से खत्म हो जाएगी।

बालों के लिए राइस वॉटर रिस का इस्तेमाल कैसे करें?

बाल धोने के बाद सही तरीके से राइस वॉटर रिस करने से बालों में गजब की चमक आती है और बालों का टूटना भी कम होता है। आइए आपको बताते हैं कैसे घर पर फर्मेंटेड राइस वॉटर को तैयार करें।

फर्मेंटेड राइस वॉटर तैयार करने का आसान तरीका

- ▶ सबसे पहले आप आधा कप चावल लें और उन्हें साफ पानी से दो-तीन बार अच्छी तरह से धो लें।
- ▶ इसके बाद चावल में 2 कप साफ पानी डालकर भिगो दें।
- ▶ फिर इसे ढक्कर कम से कम 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
- ▶ अब 24 घंटे के बाद पानी को छानकर किसी साफ से बोतल या बर्तन में निकाल लें। आपका



फर्मेंटेड राइस वॉटर तैयार हो जाएगा।

राइस वॉटर इस्तेमाल करने की सही स्टेप-बाय-स्टेप विधि

राइस वॉटर का सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

शैम्पू से बाल धोकर राइस वॉटर लगाएं

- ▶ सबसे पहले आप अपने बालों की किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लें।
- ▶ फिर बाद में गीले बालों पर ही तैयार किया गया राइस वॉटर को डालें।
- ▶ इसे बालों की जड़ों से लेकर नीचे सिरों तक अच्छे लगाएं। स्प्रै बोतल की मदद से इसे लगाना काफी आसान होगा।

स्कैल्प की मसाज करें

- ▶ राइस वॉटर लगाने के बाद कम से कम 3 से 5

मिनट तक रुकें और फिर हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें।

- ▶ मालिश करने के बाद इस पानी को बालों में 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें।
- ▶ फिर सादे पानी से बालों को अच्छी तरह से धो लें। इस बात का ध्यान रखें कि दोबारा शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

बालों में राइस वॉटर रिस करने के बेहतरीन फायदे

- ▶ इसमें प्रोटीन होता है, जो बालों का लचीलापन सुधार देता है और इन्हें बीच से टूटने से बचाता है।
- ▶ नियमित इस्तेमाल से दोमुंहे बालों की समस्या कम होने लगती है।
- ▶ बिना किसी केमिकल वाले महंगे कंडीशनर के भी आप अपने बालों को स्मूथ और चमकदार बना सकते हैं।

साड़ी में पतला और लंबा दिखने के लिए अपनाएं ये 3 आसान फैशन हैक्स

साड़ी में पतला और लंबा दिखने के लिए ड्रेपिंग का सही तरीका बेहद महत्वपूर्ण है। सही पल्लू लेंथ, पतली बॉर्डर की साड़ी और वर्टिकल प्रिंट्स का चुनाव करके महिलाएं आसानी से एक आकर्षक और स्लिम लुक हासिल कर सकती हैं। इन आसान फैशन हैक्स का विश्लेषण करके आप अपनी हाइट को बेहतर और बॉडी शेप को परफेक्ट दिखा सकती हैं।

हर भारतीय नारी साड़ी परिधान में बेहद खूबसूरत नजर आती है। साड़ी पहनने की चाहत हर किसी लड़की को होती है। ऐसे में लड़कियां चाहती हैं कि वह साड़ी में लंबी और पतली नजर आए। हालांकि हर बार साड़ी को गलत तरीके से पहनने के कारण लुक खराब हो जाता है। ऐसे में कई महिलाएं अच्छी-खासी हाइट होने के बावजूद वह छोटी नजर आती है। अब आप इन तरीकों से साड़ी पहनेंगे, तो आप पतली और लंबी नजर आएंगी।

पल्लू को लंबा और सीधा रखें

अक्सर कई महिलाओं को साड़ी खुले पल्लू के साथ कम पसंद होती है। वह प्लेट्स लगाकर साड़ी पहनना पसंद करती हैं। यदि आप इस तरह से साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो प्लेट्स को बहुत ज्यादा चौड़ी या लंबी न बनाएं।

- ▶ इसके लिए पल्लू की प्लेट्स पतली और बराबर रखें, तो अच्छा है।
- ▶ पल्लू का ज्यादा छोटा न रखें।
- ▶ कंधे पर इसे अच्छी तरह पिन करें।
- ▶ पल्लू को कमर पर ज्यादा फैलाएं नहीं।
- ▶ पल्लू पर बना बॉर्डर भी सीधा रखें।

पतली बॉर्डर वाली साड़ी का चयन करें

जब आप साड़ी का पहनें, तो इसका सही चयन करना काफी जरूरी है। बहुत अधिक चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी में कितनी भी पतली प्लेट्स



बना लें, बॉर्डर को मोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए पतली बॉर्डर वाली साड़ी का चयन करें। वहीं, पतली बॉर्डर वाली साड़ी में आप लंबी और पतली दिखाई देंगी।

- ▶ ध्यान रखें कि बॉर्डर को प्लीट्स में ज्यादा मोड़ने से बचें।
- ▶ वर्टिकल या लंबी डिजाइन वाली साड़ी में आप लंबी जरूर दिखेंगी।
- ▶ छोटे और बिखरे हुए प्रिंट के बजाय स्ट्रेट पैटर्न ट्राई करें। शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका

पल्लू खुला रखना रहेगा बेस्ट

अगर आप साड़ी में लंबी और पतली दिखना चाहती हैं, तो खुले पल्लू में साड़ी कैरी करना काफी फायदेमंद हो सकता है।

- ▶ पल्लू की लंबाई घुटने के आसपास या उससे नीचे तक रखें।
- ▶ कंधे पर पल्लू को हल्का पीछे की तरफ सेट कर लें।
- ▶ सामने से पल्लू की सीधी लाइन बनी रहना जरूरी है।



भेड़ाघाट की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग, चट्टानों से झरने तक सब है खास



संदीप कुमार

अगर आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ विदेशी नजारों वाला एहसास करा सके। तो आपको एक बार मध्यप्रदेश का रुख करना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी खूबसूरत जगह है, जिसको देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस जगह का नाम भेड़ाघाट है। यह जगह हरे-भरे पेड़ों और संगमरमर की ऊंची-ऊंची चट्टानों से घिरा है। भेड़ाघाट को फिल्मों की शूटिंग और बोटिंग आदि के लिए परफेक्ट माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भेड़ाघाट की खासियत के बारे में बताने जा रहे हैं।



भेड़ाघाट की खासियत

इस जगह की खासियत यहां की 100 फीट ऊंची चट्टानें हैं। नर्मदा नदी के तेज बहान ने इन चट्टानों को 5 किमी लंबी खूबसूरत घाटी में बदल दिया। वहीं लोग इन चट्टानों को जादुई मानते हैं। जैसे-जैसे पानी का बहता है, इन चट्टानों का आकार बदलता है। बाहर से काली और अंदर से सफेद दिखने वाली इन चट्टानों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। रात के समय चांद की रोशनी में इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती है।

जमीन में दबे हैं सालों पुराने राज

यह जगह भूगोल के नजरिए से भी बेहद खास है। नर्मदा और ताप्ती दोनों देश की वह दो नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी की जगह अरब सागर में गिरती है। एक जमाने पर यहां जमीन में दरार आ गई थी। जिससे बीच की जमीन रह गई और दोनों नदियां अरब सागर की ओर बहने लगीं।

अरबों साल पहले यहां पर ज्वालामुखी फटा था, उस ज्वालामुखी के लावे से 'सॉफ्ट स्टोन' बना था। जिसको हम मार्बल बोलते हैं, यह वही सॉफ्ट स्टोन है। इसमें मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इस कारण यह इतना नर्म होता है। वहीं इसी इलाके में डायनासोर के अंडे भी मिल चुके हैं।

धुंधाधार वॉटरफॉल्स

भेड़ाघाट में एक फेमस और बहुत सुंदर वॉटरफॉल भी है, जिसको 'धुआंधार वॉटरफॉल्स' के नाम से जाना जाता है। इस वॉटरफॉल का नाम ही इसकी खूबसूरती को बयां कर देता है। यहां पर पानी इतनी तेज रफ्तार और ऊंचाई से गिरता है कि चारों ओर पानी की बूंदें धुएँ की तरह उड़ती दिखती हैं। यहां बहते पानी का शोर बहुत दूर तक सुनाई देता है।

फिल्मों की फेवरेट लोकेशन

बॉलीवुड को भी भेड़ाघाट की खूबसूरती बेहद लुभाती है। शाहरुख खान और तापसी पन्नू स्टारर सुपरहिट फिल्म 'डंकी' में भेड़ाघाट के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी इस जगह पर कई यादगार फिल्मों फिल्माई गई हैं। जिनमें रितिक रोशन की फिल्म मोहनजोदड़ो, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की फिल्म बाँबी, सुनील दत्त की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए और शोमैन राज कपूर की क्लासिक फिल्म 'जिस देश में गंगा बहती है' शामिल है।



चौसठ योगिनी मंदिर

यहां पर घूमने के दौरान आप चौसठ योगिनी मंदिर भी देखने जरूर जाएं। नर्मदा नदी के ठीक ऊपर बने एक पहाड़ पर यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में मां दुर्गा की 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों के बीचोबीच में भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान है।

बैलेसिंग रॉक्स

भेड़ाघाट में आपको नेचर का एक और सरप्राइज देखने को मिलता है, जिसको बैलेसिंग रॉक्स कहते हैं। यह पत्थर की काफी बड़ी गोलाकार चट्टानें हैं। जिनको इंसानों ने नहीं बनाया। यह चट्टानें हजारों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट से बनी थीं। इसकी खासियत इनका बैलेस है। चाहे भूकंप आए या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, इन गोलाकार चट्टानों का बैलेस कभी नहीं बिगड़ता है।

ऐसे पहुंचें भेड़ाघाट

जबलपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से करीब 25 किमी दूर यह जगह है।

अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें, तो जबलपुर शहर का अपना एयरपोर्ट भी है।

इसके अलावा भेड़ाघाट तक आने के लिए पर्यटकों के पास रोपवे का ऑप्शन भी है। वहीं मार्बल रॉक्स और घाट के नजारों को करीब से महसूस करने के लिए आप नर्मदा नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं।

‘इतना गुस्सा क्यों?’ सड़क पर कुछ सेकंड की देरी हमारे शरीर के साथ क्या करती है

एक धीमा राइट टर्न, कुछ सेकंड का इंतजार और फिर एक बुजुर्ग चालक पर हाथ उठ जाना। रोड रेज की जड़ अक्सर सड़क पर नहीं, हमारे भीतर होती है।



सिर्फ एक राइट टर्न था। कुछ सेकंड की देरी थी। एक कार थोड़ी धीमी थी। लेकिन अगले ही पल सड़क पर गुस्सा, बहस और हिंसा दिखाई देने लगी।

कल रात (शहर/इलाके का नाम) में मैंने सड़क पर एक ऐसी घटना देखी, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कार से मोड़ ले रहे थे। पीछे से एक युवक अपनी महंगी कार में उसी दिशा में राइट टर्न लेना चाहता था। बुजुर्ग चालक थोड़ा धीरे मुड़े, और बस यहीं से कहानी बदल गई।

युवक अचानक आक्रामक हो गया। आवाजें तेज होने लगीं। उसने बुजुर्ग चालक से कहा, ‘अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी बेच दो।’



डॉ. शुभम भारद्वाज

शुरूआत में यह सड़क की आम बहस जैसी लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में युवक ने बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी।

एक पल के लिए सोचिए। न कोई दुर्घटना हुई थी, न किसी की जान खतरे में थी। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसे कुछ सेकंड इंतजार करके संभाला न जा सके। फिर ऐसा क्या था जिसने एक इंसान को दूसरे पर हाथ उठाने तक पहुंचा दिया?

शायद वह कुछ सेकंड की देरी नहीं थी। शायद समस्या हमारे भीतर बढ़ता हुआ गुस्सा, अधीरता और अहंकार है।

छोटी बात, बड़ा झगड़ा

रोड रेज अक्सर किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होता। कभी एक हॉर्न से, कभी किसी के अचानक लेन बदलने से, कभी किसी के धीरे चलने से। और कभी सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमें कुछ सेकंड इंतजार करा दिया।

सवाल यह है कि क्या सड़क पर हर छोटी गलती हमारे अहंकार की लड़ाई बन जानी चाहिए?

उन कुछ सेकंड में शरीर में क्या होता है

जब हमें लगता है कि किसी ने हमारा रास्ता रोका या हमें चुनौती दी, तो दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। शरीर 'लड़ो या भागो' वाली स्थिति में आ जाता है। एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, दिल की धड़कन और रक्तचाप तेज हो जाते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं।

इस उत्तेजना में सोच-समझकर फैसला लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और प्रतिक्रिया आवेग से होने लगती है। यही वजह है कि गुस्से में लोग वह कर बैठते हैं, जिस पर बाद में पछताते हैं। अच्छी बात यह है कि यह उबाल कुछ समय में उतरने लगता है। अगर उन शुरूआती पलों में खुद को रोक लिया जाए, तो अधिकतर विवाद वहीं खत्म हो सकते हैं।

गुस्से पर काबू के छह उपाय

गुस्सा एक सामान्य भावना है। समस्या तब शुरू होती है जब वह हमारे फैसलों पर हावी होने लगे। ड्राइविंग के दौरान कुछ सेकंड का आत्म-नियंत्रण किसी बड़ी दुर्घटना या हिंसा को रोक

सकता है।

10 सेकंड रुकिए: गुस्सा बढ़ता लगे तो तुरंत जवाब देने के बजाय गहरी सांस लेकर 10 सेकंड रुकें। खुद से पूछें, 'क्या यह बात 10 मिनट बाद भी इतनी अहम रहेगी?' अक्सर जवाब 'नहीं' होगा।

बहस जीतने की कोशिश न करें: किसी को गलत साबित करना सुरक्षित घर पहुंचने से ज्यादा जरूरी नहीं है। सामने वाला गुस्से में हो, तो दूरी बनाना ही समझदारी है।

हॉर्न और गाली को हथियार न बनाएं: लगातार हॉर्न, गाली, पीछा करना या रास्ता रोकना आग में घी डालता है। शांत प्रतिक्रिया अक्सर विवाद वहीं खत्म कर देती है।

शरीर के संकेत पहचानें: तेज धड़कन, कसी मुट्ठियां, ऊंची आवाज या शरीर में तनाव, यही रुकने का समय है, जवाब देने का नहीं।

कुछ देर के लिए रुक जाएं: लगे कि नियंत्रण छूट रहा है, तो सुरक्षित जगह गाड़ी रोकें। कुछ गहरी सांस लें, पानी पिएं, फिर आगे बढ़ें।

बार-बार गुस्सा आए तो मदद लें: छोटी बातों पर बार-बार तेज गुस्सा, चीजें तोड़ने, धमकाने या मारपीट करने का मन होना, इसे 'मेरा स्वभाव ही ऐसा है' कहकर न टालें। किसी मानसिक स्वास्थ्य

विशेषज्ञ या एंगर मैनेजमेंट काउंसलर से बात करें।

अगर कोई आप पर हमला करे या धमकाए, तो गाड़ी के शीशे और दरवाजे बंद रखें, बाहर न निकलें और 112 पर कॉल करें। किसी और के साथ ऐसा होते देखें, तब भी 112 पर सूचना दें।

सड़क सबकी है

सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यहां युवा भी हैं, बुजुर्ग भी; अनुभवी चालक भी और वे भी जिन्हें थोड़ा अधिक समय लगता है। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन एक छोटी गलती को हिंसा में बदलने का फैसला हमारे हाथ में होता है। हम कार की स्पीड, ब्रेक और इंजन की ताकत पर ध्यान देते हैं। लेकिन ड्राइविंग की एक और क्षमता है, जिसकी कोई मशीन जांच नहीं करती: गुस्से पर नियंत्रण। एक तेज कार कुछ सेकंड में रफतार पकड़ लेती है, पर गुस्सा उससे भी तेज बढ़ सकता है। अच्छी ड्राइविंग का मतलब सिर्फ जल्दी मंजिल तक पहुंचना नहीं है। असली ड्राइविंग यह है कि हम मंजिल तक पहुंचें, लेकिन रास्ते में अपना धैर्य, विवेक और इंसानियत पीछे न छोड़ें।



रामदूत अतुलित बल धामा...



संदीप कुमार



हनुमान अंश

सिनेमा मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बनकर उभरा है। इससे पहले किस्सागोई, कहानीआदि मनोरंजन के साधन रहे। फिर नाटक समाज में आया, नाटक को अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। नाटक मनोरंजनपरक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक कथाओं आदि को लेकर बने। यह लोगों के बीच लोकप्रिय भी रहे। नाटक मंच पर खेला जाता है। पहले नाटक में नारी पात्र की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे। फिर धीरे-धीरे नारी पात्र के रूप में नारियों ही आने लगी। नाटक में गीतों का भी गया जाना महत्वपूर्ण रहा। धीरे-धीरे तकनीक का युग आया तो नाटक की जगह धारावाहिकों ने ले ली लेकिन रंगमंच पर नाटक आज भी खेले जा रहे हैं।

इसी के साथ ही सिनेमा अर्थात फिल्में तेजी से बनने लगी। फिल्में भी अलग-अलग विषयों को लेकर बनाई जाने लगी। वर्तमान में हिंदी सिनेमा अर्थात फिल्मों ने एक लंबी यात्रा पूरी कर ली है। तकनीक का प्रयोग भी बहुत तेजी से फिल्मों में बढ़ रहा है। फिल्मों पर होने वाला खर्च भी बढ़ रहा है। फिल्मों को देखने वाले दर्शक भी अलग-अलग तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। उसी के आधार पर सिनेमा भी बन जाता है। हाल ही में फिल्म हनुमान अंश प्रसारित हुई। फिल्म ना बड़े बजट की है और ना ही फिल्म में फिल्मी दुनिया का कोई बड़ा सितारा काम कर रहा है। ना ही फिल्म में कोई बड़ा संगीतकार और गायक है। फिर भी फिल्म ने कमाई के मामले में बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की शुरुआत धीमी रही लेकिन देखते ही देखते फिल्म लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी।

यह फिल्म भारतीय आस्था, भक्ति, साधना, अध्यात्म, ज्ञान, संस्कृति, संत ज्ञान परंपरा से सीधी जुड़ी हुई है। संत के दर्शन, संत की संगत, संत



का भाव, संत का चरित्र, संत का समाज में महत्व आदि विशेष गुणों को बताती, समझती और दिखाती है। फिल्म में गाने नहीं बल्कि भजन को गया गया है। फिल्म में लोकप्रिय भजनमैंने तेरे ही भरोसेझुप्रज्ञा चक्षु के कंठ से निकाला और फिल्म का हिस्सा बन गया। विचार करें तो संत सभी को साथ लेकर चलते हैं।

भारतीय सिनेमा समयानुसार पौराणिक आख्यानों और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से पर्दे पर प्रस्तुत करता रहा है। हनुमान अंश फिल्म संत जीवन पर बनी है। यह फिल्म

हमारी संत और ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास करती है। फिल्म में संत द्वारा भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति, साधना को दिखाया गया है। फिल्म में हनुमान जी की भक्ति को महज एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने के एक आदर्श मार्ग के रूप में दिखाया गया है। यह दर्शकों को संदेश देती है कि मन में विश्वास और धर्म का मार्ग अपनाने से बड़ी से बड़ी बाधाओं पर विजय पाई जा सकती है।

बदलते दौर में लोगों को कई बार ऐसा भी

लगता है कि तेजी से बदलते युग में हमारी युवा पीढ़ी अपने सांस्कृतिक जीवन से दूर होती जा रही है। ऐसे में सिनेमा के रुपहले पर्दे पर हनुमान अंश का फिल्म का आना और लोगों का इसे पसंद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 'हनुमान अंश' फिल्म सुपरहीरो संस्कृति के दौर में हमारे संतोकी महत्ता, ज्ञान, शक्ति, महानता को सामने लेकर आई है। इससे युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व और सम्मान की भावना जागृत हुई है। इस फिल्म को लोग बढ़ चढ़कर अपने परिवार के साथ, मित्र मंडली के साथ देखने सिनेमाघरों में जा रहे हैं।

बहुत से लोग तो फिल्म के शुरू होने और बाद में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। फिल्म भक्ति और आस्था को जागृत करती है। यह फिल्म हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिखाती है। सत्य यह भी है कि जब भी समाज पथ भ्रमित होता है, उसमें भ्रांतियाँ पैदा होती हैं तो संत ही समाज को सही मार्ग पर आगे लेकर चलते हैं। संत जीवन पर बनी इस फिल्म ने सभी को पीछे छोड़ दिया है और नकारात्मक सिनेमा को उत्तर दे दिया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय जीवन शैली आज भी अपनी पौराणिक मान्यताओं, आस्था आदि के साथ रहने वाली है।



फिल्म की सफलता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले मेकर्स



'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म भारत में 150 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच गई है। इसी बीच फिल्म को रिलीज हुए 33 दिन पूरे हो गए हैं और इसकी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास पर मुलाकात की।

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी, प्रोड्यूसर और फिल्म की स्टारकास्ट के कुछ सदस्य मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। इस दौरान टीम ने सीएम योगी के साथ फिल्म बनाने के अपने अनुभव शेयर किए और फिल्म से जुड़ी कई बातें कीं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस मुलाकात

की तस्वीरें भी शेयर की हैं। मुलाकात के दौरान फिल्म और इसके कुछ खास सीन्स पर चर्चा हुई। इन सीन्स में नीम करौली बाबा और नाथ संप्रदाय की परंपरा से जुड़े प्रसंग दिखाए गए हैं। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म की एक आध्यात्मिक परंपरा है, जिसका संबंध भगवान शिव से माना जाता है। यह परंपरा योग, ध्यान और साधना पर खास ध्यान देती है। फिल्म की टीम के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने फिल्म के उन महत्वपूर्ण सीन्स को भी देखा, जिनमें गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की परंपरा का जिक्र किया गया है। फिल्म में नीम करौली बाबा और नाथ परंपरा से जुड़े संतों के बीच के गहरे संबंध को भी दिखाया गया है।



राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन, 13 स्वर्ण सहित जीते 39 पदक



राजीव चौधरी

भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। भारतीय दल पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा और मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, जूडो तथा भारोत्तोलन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

मुक्केबाजी भारत के लिए सबसे सफल खेल साबित हुआ। भारतीय मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और तीन रजत सहित दस पदक जीतकर इस खेल की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। किसी एक राष्ट्र द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के एक संस्करण में सात मुक्केबाजी स्वर्ण जीतने का यह नया रिकॉर्ड बना। सचिन, अंकुश, साक्षी, प्रीति, जैस्मिन, प्रिया और अरुंधति चौधरी ने अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए।

जूडो में भी भारत ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम और हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत को राष्ट्रमंडल खेलों के जूडो इतिहास में उसके पहले दो स्वर्ण पदक दिलाए।



यामिनी मौर्या ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर इस उपलब्धि को और यादगार बनाया। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल स्वर्ण जीतकर अपनी श्रेष्ठता कायम रखी। वल्लूरी अजय बाबू और लवप्रीत सिंह ने अपने वर्गों के स्नैच मुकाबलों में राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड भी स्थापित किए। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादु गावित, सोमन राणा और शर्मिला

ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि नीरज चोपड़ा सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदकों के साथ देश का गौरव बढ़ाया। ग्लासगो में मिली सफलता ने भारतीय खेलों की बढ़ती ताकत और प्रतिभाओं की व्यापकता को प्रदर्शित किया। वर्ष 2030 में अहमदाबाद में प्रस्तावित शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों से पहले यह प्रदर्शन भारत की तैयारियों और पदक संभावनाओं के लिए मजबूत आधार बनकर सामने आया है।



स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

महिला क्रिकेट की नई रन मशीन

भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया है।

भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है।

उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया है। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ एशिया कप 2026 मैच में शानदार शतक लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। स्मृति ने 64 गेंदों में 124 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके साथ ही वह पूर्व कप्तान मिताली राज के 10,868 इंटरनेशनल रनों के रिकॉर्ड से आगे निकल गईं। इस पारी के बाद मंधाना के करियर के कुल रन 10,880 हो गए हैं और वह अब इस लिस्ट में टॉप पर हैं। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 10,740 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

- ▶ स्मृति मंधाना - 10880 रन
- ▶ मिताली राज - 10868 रन
- ▶ सूजी बेट्स - 10740 रन
- ▶ शार्लेट एडवर्ड्स - 10273 रन
- ▶ स्टेफनी टेलर - 10007 रन

खास बात यह रही कि स्मृति ने शतक पूरा करने के तुरंत बाद रुचिथा वेंकटेश की गेंदों पर लगातार तीन

छक्के जड़े। उनकी पारी आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर रन आउट होने पर खत्म हुई, लेकिन तब तक वह भारत को 193 रनों तक पहुंचा चुकी थीं।

18वां शतक, मेग लैनिंग को भी पीछे छोड़ा

यह रिकॉर्ड मंधाना के शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि है। इसी पारी में उन्होंने अपना 18वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के 17 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब महिला T20 एशिया कप में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्होंने 2024 में मलेशिया के खिलाफ चमारी अथापथु के नाबाद 119 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

हरमनप्रीत का छक्कों का रिकॉर्ड भी टूटा

हांगकांग के खिलाफ स्मृति ने 7 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने T20I में भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उनके नाम T20I में 95 छक्के हैं, जबकि हरमनप्रीत के 89 छक्के हैं।



महिला T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के

- ▶ स्मृति मंधाना - 95
- ▶ हरमनप्रीत कौर - 89
- ▶ शोफाली वर्मा - 87
- ▶ रिचा घोष - 46
- ▶ जेमिमा रोड्रिग्स - 28

महिला T20 एशिया कप में सबसे बड़ा स्कोर

- स्मृति मंधाना बनाम हांगकांग - 124 रन
- चमारी अथापथु बनाम मलेशिया - 120 नाबाद
- मिताली राज बनाम मलेशिया - 97 नाबाद
- हर्षिता समरविक्रमा बनाम थाईलैंड - 81 रन
- शोफाली वर्मा बनाम नेपाल - 81 रन



एनसीआर में एयर टैक्सी नेटवर्क की तैयारी शहरी परिवहन को मिलेगी नई दिशा



विजय द्विवेदी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और शहरों के बीच तेज संपर्क विकसित करने के लिए एयर टैक्सी आधारित परिवहन व्यवस्था की योजना तैयार की जा रही है। एनसीआर योजना बोर्ड ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एयर टैक्सी, ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करने की संभावनाओं पर काम शुरू किया है।

योजना के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के प्रमुख शहरों तथा जिला मुख्यालयों में वर्ष 2030 तक एयर टैक्सी और

अगले दशक में विकसित होने वाली एयर टैक्सियों के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन, हाइड्रोजन फ्यूल-सेल तकनीक, विशेष चार्जिंग सुविधाएं और सुरक्षित ऊर्जा भंडारण प्रणाली तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

यूएवी के लिए सुरक्षित लैंडिंग, टेक-ऑफ एवं पार्किंग सुविधाएं विकसित करने की सिफारिश की गई है। इन केंद्रों को वटीपीए के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों के साथ सामान और कूरियर सेवाओं का संचालन भी संभव होगा।

एयर टैक्सी नेटवर्क को हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट व्यवस्था से जोड़ने की योजना है। इससे

आपातकालीन सेवाओं, कारोबारी यात्राओं, पर्यटन और वीआईपी आवागमन में तेजी आने की संभावना है। पुलिस को ड्रोन और एयर टैक्सी के माध्यम से यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा निगरानी में भी सहायता मिल सकेगी। अगले दशक में विकसित होने वाली एयर टैक्सियों के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन, हाइड्रोजन फ्यूल-सेल तकनीक, विशेष चार्जिंग सुविधाएं और सुरक्षित ऊर्जा भंडारण प्रणाली तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और कम प्रदूषण वाली तकनीकों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विमानन सुरक्षा मानकों, परिचालन नियमों और नियामकीय ढांचे का निर्माण आवश्यक होगा। बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था विकसित होने के बाद एयर टैक्सी एनसीआर की परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है।

TCL

GRAND INDEPENDENCE DAY UPGRADE

7th - 16th AUGUST 2026



FREE

1-YEAR EXTENDED WARRANTY*

SAVE UP TO ₹24,990*

10% CASHBACK

UP TO

₹15,000*



C7L SQD-Mini LED TV

Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch), 215cm (85 inch), 248cm (98 inch)

- 100% BT-2020
- All Scenes Wide Color Gamut
- Up to 2175 Precise Dimming Zones
- HVA 3.0 Pro Panel
- Up to HDR 3000nits



A400 Pro NXTVISION TV

Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch)

- Frame Design
- Art Gallery
- QD-MiniLED
- Matte Screen



C8L SQD-Mini LED TV

Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch), 215cm (85 inch), 248cm (98 inch)

- Ultra Slim Design
- HVA 3.0 Ultra Panel
- 100% BT-2020
- All Scenes Wide Color Gamut
- Precise Dimming Series Up to 2175 zones



P8L Premium QD-Mini LED TV

Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch), 215cm (85 inch), 248cm (98 inch)

- Precise Dimming Series
- 144Hz Native Refresh Rate
- High HDR Brightness
- ONKYO

T&C Apply*



Agro Zone Agra, Mathura, Firozabad, Meerut, (Anil Deyani - 915280075)

Beauty Zone Bareilly, Budan, Pilibhit, Shahjahanpur, (Deepak Singh - 892356546)

Meerut Zone Meerut, Baghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar (Noida), Ghaziabad,

Hapur, (Anuj Gupta - 9548285247)

Kanpur Zone Kanpur, Etawah, Faramukabad, Kannauj, Kanpur Dehat, (Fahimuddin - 8318071391)

Lucknow Zone Lucknow, Haridoi, Lalitpur, Kheri, Raebareilly, Sitapur, Unnao, (Prem Pandey - 8009212363)

Prayagraj Zone Prayagraj, Fatehpur, Kaushambi, Pratapgarh, (Prasoon Chauhan - 9369417110)

Varanasi Zone Varanasi, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur, (Manoj Kumar Yadav - 9721450046)

Gorakhpur Zone Gorakhpur, Kushinagar, Maharajganj, Deoria, (Akashmani Tripathi - 9938863366)

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW

25TH-29TH
SEPTEMBER, 2026

4TH
EDITION

INDIA EXPO CENTRE & MART, GREATER NOIDA



एक जनपद
एक उत्पाद

75 उत्पादों को
वैश्विक पहचान

राज्य के कुल ₹2 लाख करोड़+ के
निर्यात में लगभग 50% का योगदान